



04 - वेनेजुएला के बाद वया तयुबा की बारी है



05 - कूदोपाली : पथरीली जमीन पर 'शिक्षा के फूल'



06 - प्रधानमंत्री का संकल्प, 2047 तक कोई भी बच्चा सिकल सेल से प्रभावित...



07 - विकासखंड नटेशन की ग्राम पंचायतों में कृषकों के समर्थ...

# कैबिनेट

प्रसंगवश

## देशी बीमा कंपनियों पर विदेशी कब्जा और हितग्राहियों की चिंताएं

अरविंद मोहन

सो लह मई को ठीक छह महीने हुए जब सरकार ने 'सबको बीमा, सबकी रक्षा' जैसे आकर्षक नाम से बीमा व्यवसाय को शत-प्रतिशत विदेशी पूंजी के लिए खोलने का बिल पेश किया था। और इसी 16 मई को पहली बड़ी खबर आई कि भारतीय बीमा कंपनी भारतीय अक्सर ब्रिटिश कंपनी प्रूडेन्शियल के हवाले हो गई। मिलिक्यत के साथ मैनेजमेंट भी उसके हाथ आ गया है। इस बदलाव की नींव पिछले साल के बजट से पड़ी थी और संसद के दोनों सदनों में भाजपा तथा एनडीए की जो स्थिति है उसमें इस बिल को पास कराने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं हुई। और पिछली बार भारतीय मजदूर संघ समेत की मजदूर यूनियनों और राजनैतिक दलों की तरफ से विरोध का जो स्वर सुनाई दिया था इस बार कहीं से भी चूँ की आवाज भी नहीं आई।

इसे सर्वसम्मति का मामला नहीं मानना चाहिए लेकिन मोटे अर्थों में सभी दलों में इस पर सहमति है भी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय से बार-बार बीमा निजीकरण का सवाल उठता रहा है और इसमें निवेश की सीमा 26 फीसदी, 49 फीसदी और 75 फीसदी तक बढ़ाने के साथ प्रबंधन और मुनाफा बाहर ले जाने की इजाजत देने के सवाल भी उठते रहे हैं। हां अभी तक एक ही मामले में सहमति नहीं बनी है कि बीमा प्रीमियम के पैसे विदेश जाने की अनुमति नहीं है। उदारिकरण की आर्थिक नीतियों पर हमारे राजनैतिक दलों में एक सर्वसम्मति सी बन गई थी और है भी। पर

बीमा के सवाल पर एक झिझक सी रही है। इसका कारण यह है कि राष्ट्रीयकरण के पहले देश में जो निजी बीमा कंपनियां थीं, उनके काम को लेकर काफी शिकायतें थीं और उनका दायरा भी बहुत सीमित था। जब से सारी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद से बीमा का दायरा बढ़ा, क्लेम निपटान का रेट सुधारा, लोगों की शिकायतें कम हुईं और सबसे बढ़कर यह बात हुई कि प्रीमियम का पैसा सरकार के हाथ आया जिससे विकास की अनेक योजनाओं के लिए रेडी कैपिटल मिला।

कई बार सरकारी निर्देश से बीमा कंपनियों की पूंजी का नारा भी हुआ, लेकिन ऐसे अवसर कम आये। यूटीआई घोटाले में जरूर बीमा निगम की पूंजी के सहारे संकट निपटारा गया। और आज भी क्लेम निपटान के मामले में हमारी पांचों सरकारी कंपनियों ही पहले पांच पायदानों पर हैं। निजी और विदेशी कंपनियों का नंबर इनके बाद ही आता है। कहना न होगा कि विदेशी कंपनियों की मजबूत लीगल टोलियां और चंट वकील गरीब ग्राहकों का क्लेम रोकने में सफल हो जाते हैं।

और अपने यहां बीमा के नाम पर उदारीकरण वाले दौर में जो 'घोटाले' हुए हैं वह भी कई बार राजनेताओं और उनसे भी बढ़कर ट्रेड यूनियन नेताओं को इसके खिलाफ पोजीशन लेने के लिए मजबूर करते हैं। बीते काफी समय से फसल बीमा और हेल्थ बीमा की चर्चा राजनीतिक हलके में ज्यादा रही है, अंडरराइटिंग क्या बला है या बड़े सौदे कैसे होते हैं, यह तो ठीक से पता भी नहीं है। लेकिन जो फसल बीमा और स्वास्थ्य बीमा योजनाएं चली हैं उनका अनुभव यह रहा है कि जितनी

रकम बीमा के प्रीमियम के रूप में दी जाती है उसका दस फीसदी भी भुगतान क्लेम के रूप में नहीं हुआ है। और इस प्रीमियम की वसूली भी सिर्फ एक ग्राहक-सरकार से लेनी हो तो कंपनियों की पौ बारह हो जाती है। उल्लेखनीय है कि ऐसे सारे कार्यक्रमों में निजी बीमा कंपनियों को ही ज्यादा अवसर दिया गया है। और कई बार लगता है कि यह भ्रष्टाचार का एक नया अध्याय है जो उदारीकरण और बीमा निजीकरण के साथ आया है। जब बीमा कंपनी और मंत्री/सचिव में डील हो गई तो किसान हो या मरीज उस बेचारे की क्या औकात रह जाती है क्लेम लेने की। और जनता के कर का पैसा होने से शोर मचाने वाले भी सामने नहीं आते। अपने यहां क्लेम का मामला तब सामने आता है जब ग्राहक सीधे कंपनी को प्रीमियम देते हैं और उनको सेवा मिलने में या पॉलिसी मैच्योर होने पर पैसे वापस पाने में मुश्किल आती है। अपने यहां सबसे ज्यादा झमेला किसी और योजना में पॉलिसी देने का वायदा करके एजेंट कंपनी की सुविधा के अनुसार दूसरी योजना में पैसे डाल देने का है। ऐसा अक्सर बाजार में निवेश के म्यूचुअल फंड के खेल में किया जाता है। और वह जब पूंजी डूबती है तो ग्राहक का सिर कुचला जाता है। ऐसी शिकायतें आम हैं लेकिन उनका निपटारा द्या से नहीं होता और शिकायतों का क्रम बढ़ता जा रहा है। सरकारों को बीमा व्यवसाय को विदेशी निवेश के लिए खोलने की जल्दबाजी तो रही है लेकिन ग्राहकों की शिकायत निपटाने का होश नहीं रहता। और कंपनियों किन वायदों के साथ आती हैं और उनका काम किस दिशा में जाता

है यह चेक करना तो सरकार अपनी जवाबदेही मानती ही नहीं, बीमा प्रोडक्ट की वेराइटी बढ़ाना और ग्राहकों के सामने नए विकल्प आना हुआ भी है या नहीं कोई नहीं देखता। देश की बीमा कंपनियों वाले दौर से आगे कितनी प्रगति हुई है, सौ फीसदी मिलिक्यत सौंपने से पहले इस पर विचार हुआ हो, ऐसा नहीं लगता।

लेकिन जिस चीज की असली चर्चा होनी चाहिए वह इन कंपनियों से मिलने वाले बीमा के दायरे का है। वह विदेशी नाम या बड़े ब्रांड का बीमा तो करेंगे लेकिन देसी और छोटे उद्यमियों के उत्पाद बीमा के दायरे से बाहर हो जाते हैं, इसे अभी सबसे अच्छी तरह बीमारी के इलाज के मिलसिले से समझा जा सकता है। नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों और बीमा कंपनियों का गठजोड़ हम सबके अनुभव के दायरे की चीज है। कल को मकान, दुकान, फर्नीचर, बरतन-बासन और हर चीज के बीमा में यह भेद दिखेगा और लगेगा कि विदेशी बीमा कंपनियां कुछ खास संगी साधियों की मदद करने आई हैं- आम लोगों से उनका कोई मतलब नहीं है। पर इससे भी ज्यादा घातक बात निवेश वाली कंपनियों का चुनाव है जो बहुत स्पष्ट दंड से पक्षपात बढ़ाती हैं। पैसा हमारा आपका और निवेश का फ्रैसला इन कंपनियों के हाथ में जाने से कुछ कंपनियों की आश्चर्यजनक तेज वृद्धि का रहस्य समझा जा सकता है। सो वे तो शत-प्रतिशत विदेशी मिलिक्यत के लिए बेचैन रही होंगी ही, हमारी सरकारें क्यों निरंतर उनका मिशन आगे बढ़ाने में लगी रही हैं, यह समझना खास मुश्किल नहीं होना चाहिए। (सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

## एक से 15 जून के बीच होंगे तबादले

● पति-पत्नी की पोस्टिंग एक जगह रखने पर विचार होगा; गंभीर बीमार कर्मचारियों को भी रियायत

प्रदेश के विकास और जन-कल्याण को गति देने के लिए 30,055 करोड़ रुपये की कैबिनेट स्वीकृति



भोपाल (नप्र)। डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार की तबादला नीति-2026 को मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में राज्य और जिला स्तर पर कर्मचारियों और अधिकारियों के 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा था। सीएम और मंत्रियों की सहमति के बाद नीति को अंतिम रूप दिया गया।

कैबिनेट ने तय किया है कि पति-पत्नी की पदस्थापना एक स्थान पर रखने के मामलों में कार्यवाही की

जाएगी। गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर्मचारियों को भी स्थानांतरण में रियायत दी जाएगी। नोटशीट में ए प्लस कैटेगरी वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ऐसे मामले तबादला नीति से बाहर रखे गए- मोहन कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि सीएम की ए प्लस नोटशीट वाले तबादले 31 मई तक करने हैं। लंबित आवेदन निपटारे जाएंगे। इसे तबादला नीति में शामिल नहीं किया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति अलग रहेगी

नई नीति में स्वेच्छिक और प्रशासनिक तबादलों की सीमा अलग-अलग तय करने का प्रस्ताव है। अब तक दोनों को एक ही कोट में शामिल किया जाता था, जिससे प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार तबादलों में बाधा आती थी। अब तक कुल कर्मचारियों के 10 से 15 प्रतिशत तक तबादलों की अनुमति दी जाती थी। इसमें स्वेच्छिक और आपसी तबादले भी शामिल होते थे, जिससे जरूरी प्रशासनिक फेरबदल प्रभावित होता था। स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति हर वर्ष की तरह अलग रहेगी। जनजातीय कार्य, राजस्व और ऊर्जा विभाग भी अलग नीति जारी कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे से अलग व्यवस्था नहीं कर सकते हैं।

भोपाल में सीएम का ऐलान

## रोजगार सहायकों के रिटायरमेंट की उम्र 62 साल होगी

भोपाल (नप्र)। भोपाल के जंजूरी मैदान पर ग्राम रोजगार सहायकों का सम्मेलन हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम डॉ. मोहन यादव ने कई घोषणाएं कीं। सीएम ने कहा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। हर सेक्टर में काम कर रहे हैं। बिना मांगे आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। सरकार आपके साथ खड़ी है। आपको जब काम का टारगेट देते हैं तो काम आप करो आपकी चिंता सरकार करेगी। ये आवधानन आपको दे रहा हूं। आप सबने पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग की थी। तो 9 हजार से बढ़कर दोगुना 18 हजार किया था। अब पंचायत सचिव के रिक्त पदों के मामले में, आयु सीमा के मामले में, अनुकंपा के मामले में आपके जनप्रतिनिधियों की बैठक कराकर ठोस निर्णय लेने वाले हैं।

रोजगार सहायकों की रिटायरमेंट उम्र 62 साल होगी- सीएम ने कहा- आपसे गांव के विकास की अपेक्षा करते



हैं। हमने रोजगार सहायकों की आयु सीमा 62 साल की है। जो बहनें रोजगार सहायक हैं उन्हें प्रसूति अवकाश, मातृत्व अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, पुरुष ग्राम रोजगार सहायक को 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा। ऐसे विषयों पर हम काम कर रहे हैं।

अपराधिक मामलों से बरी होने पर फिर मिलेगी नौकरी- सीएम ने कहा- किसी कारण से किसी रोजगार सहायक पर अपराधिक प्रकरण बन जाए और बाद में वो निर्दोष सिद्ध हो जाए तो उसे पुनः सर्विस में लेने की गारंटी हम सरकार के माध्यम से घोषणा करते हैं। जब कोई अपराध नहीं किया तो फिर क्यों बाहर करना? सबसे पहले आपके हितों के साथ सुरक्षा और सम्मान से गांव के विकास को जोड़कर देखने की दृष्टि हमने शुरू की है।

## कार ने 3 महिला धर्मगुरुओं को कुचला, एक की मौत

दो गंभीर घायल



रीवा (नप्र)। रीवा में बुधवार को कलेक्ट्रेट के सामने तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे पैदल चल रही तीन जैन महिला धर्मगुरुओं को कुचल दिया। हादसा में एक महिला धर्मगुरु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, मृत महिला धर्मगुरु की पहचान श्रुति मति माता के रूप में हुई है। वे सागर जिले की रहने वाली थीं। सतना से रीवा प्रवास पर आई थीं। हादसे में घायल हुई उपसमिति माता तमिलनाडु की निवासी हैं, जबकि आरिका माता जबलपुर की रहने वाली बताई गई हैं।

सड़क किनारे पैदल जा रही थीं धर्मगुरु- प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तीनों महिला धर्मगुरु सड़क किनारे पैदल जा रही थीं। इसी दौरान तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर उनकी तरफ आ गई और तीनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

## आरोपी ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

हादसे के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। गुस्साए लोगों ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। स्थिति तनावपूर्ण होती देख पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। कमिश्नर वीएस जामोद, डिट्टी कमिश्नर नरेंद्र सूर्यवंशी और एसपी गुरुकर सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को शांत कराने और स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास किया। हादसे के बाद पूरे जैन समाज में शोक और आक्रोश का माहौल है।

## नितिन नवीन की नई टीम में अन्नामलाई की एंट्री!

● बीजेपी की संभावित लिस्ट में कई चौकाने वाले युवा नाम

नई दिल्ली (एजेंसी)। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अगले हफ्ते अपनी नई टीम की घोषणा कर सकते हैं। उनकी टीम के जो संभावित नाम हाथ लगे हैं, उनमें ज्यादातर युवा चेहरे हैं। सबसे चौकाने वाला नाम तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और



पूर्व आईपीएस के अन्नामलाई का है। नितिन नवीन की अगुवाई में बीजेपी को पश्चिम बंगाल और असम में अप्रत्याशित जीत हासिल हुई है। पुडुचेरी में भी बीजेपी गठबंधन की सत्ता में वापसी हुई है। चुनाव से पहले पांच राज्यों में से सिर्फ दो में ही एनडीए की सरकारें थीं, अब तीन राज्यों में गठबंधन ने भगवा लहरा दिया है। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष पर गोवा और मणिपुर में चुनाव की जिम्मेदारी है।

## आर्थिक तूफान सिर पर, प्रधानमंत्री मोदी इटली में टॉफी बांट रहे

● मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट देने पर राहुल गांधी का तंज

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट की। इसका वीडियो बनाकर इटली की पीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद अब लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस पर तंज कसा। आर्थिक तूफान सिर पर है, और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर भारत से रवाना हुए थे। जिसमें वह सबसे पहले यूएई गए थे। यहां कुछ घंटे रुकने के बाद प्रधानमंत्री यूएई से नीदरलैंड के लिए रवाना हो गए थे। नीदरलैंड की यात्रा पूरी होने के बाद पीएम मोदी स्वीडन पहुंचे और इसके बाद वह नॉर्वे रवाना हो गए थे। नॉर्वे की यात्रा पूरी होने के बाद अब प्रधानमंत्री इटली पहुंचे हैं। यहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को ही उन्होंने मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट की है।



## भारत इटली

## मजबूत करेंगे रणनीतिक रिश्ते

● रोम से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, मेलोनी ने आईएमईसी पर दिया जोर

रोम (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने इटली को भारत का अहम साझेदार बताया और कहा कि हमारी बातचीत तय एजेंडे से कहीं आगे की है। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन को देशों की पार्टनरशिप की इंजन बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। इस दौरान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने इंडिया-मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को तेजी से विकसित करने पर जोर दिया।



आतंकवाद के खिलाफ भारत-इटली एक

पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और इटली एकमत हैं कि यह मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहलें ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया है। पीएम मोदी बोले- भारत और इटली ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि जिम्मेदार लोकतंत्र आतंकी नेटवर्क तोड़ने में साथ रहेंगे।

मेलोनी ने कहा ऐतिहासिक दिन

संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने पीएम मोदी को मित्र कहकर संबोधित किया और इस मुलाकात को ऐतिहासिक बताया। मेलोनी ने



कहा, आज का दिन हमारे दोनों देशों के संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मेरे मित्र नरेंद्र मोदी 2014 से भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन आज इटली की उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले किसी भारतीय पीएम की इटली यात्रा 26 साल पहले हुई थी।

subhasaverenews@gmail.com  
facebook.com/subhasaverenews  
www.subhasavere.news  
twitter.com/subhasaverenews

## शहर की सुबह

चौका और पूजा घर है एकदम साफ-सुधरा शेष घर कुछ उजड़ा-सा बहुत से घरेलू उपकरणों पर धूल जमी हुई जिन्हें जुटाने के लिए जीवन में किया अथक परिश्रम। जोड़ना नहीं है कुछ जो है वही पर्याप्त बल्कि कुछ ज्यादा ही। ताप नहीं है आग सारी बुझ चुकी शीतल जल ने जगह ले ली उसकी जिसमें निर्मल हँसी तैरती है श्वेत कमलों की तरह। शांति है यहाँ सुदूर वीराने में स्थित किसी प्राचीन मंदिर की शांति चंदन और अगरबत्ती की सुगंध सर्वत्र व्याप्त। लगभग मीन धीमी ज़िंदगी मंथर गति से होते हैं सब काम वृद्ध दंपती के घर में। आँसु के पेंड से पते एक-एक कर झरते हैं निःशब्द।

- चंद्रशेखर साकल्ले



## पीक पर गर्मी, झुलसा रहे 'लू' के थपेड़े

● अगले 7 दिन 10 राज्यों में चलेंगी गर्म हवाएं

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में गर्मी अपने पीक पर है। इस बीच मौसम एजेंसी स्काइमेट ने अरब सागर के ऊपर नया सिस्टम बनने की जानकारी दी है, जो मानसूनी हवाओं को कमजोर कर सकता है। इससे केरल समेत दक्षिण भारत में बारिश कम होने की आशंका है। एजेंसी ने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के 10 राज्यों में अगले एक हफ्ते तक सूखी-गर्म हवाएं चलेंगी। एजेंसी के मुताबिक इस दौरान इन राज्यों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री या उससे ज्यादा रहेगा। वेस्टर्न



डिस्टेंस कमजोर होने और कोई ऐक्टिव वेदर सिस्टम नहीं होने की वजह से बारिश की कोई संभावना नहीं है।

### शहरों में फील टेंपरेचर 4 सेंटीग्रेट तक अधिक

वास्तविक तापमान और फील टेंपरेचर में हर शहर में औसत 2 से 4 डिग्री तक का अंतर है। वलाइमेट एक्सपर्ट के मुताबिक, मौसम विभाग जो तापमान बताता है, लोगों को उससे कहीं ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण तेजी से होता शहरीकरण है। इससे तापमान में उछाल आ रहा है। फील फेक्टर तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत को भिगोने वाले दक्षिणी-पश्चिमी मानसून ने मंगलवार को कोमरिन सागर, श्रीलंका, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिमी भाग के कुछ और हिस्सों को कवर कर लिया।

### यूपी में अगले 5 दिनों तक चलेगी हीटवेव

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक पूरे प्रदेश में गर्मी रहेगी। आज हीटवेव का 11 जिलों में रेड, 14 जिलों में ऑरेंज और 28 जिलों में यलो अलर्ट है। ज्यादातर जिले लू की चपेट में रहेंगे। 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी। दिन का तापमान 44 से 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं राजस्थान में गर्मी और हीटवेव का असर तेज हो गया है। सिराही को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में मंगलवार को अधिकतम तापमान 40 से 47 डिग्री के बीच रहा। जयपुर में रात की गर्म बनी हुई है। मंगलवार को यहां मिनिमम तापमान 31.3 रहा। बिहार में आज 33 जिलों में आंधी-बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में ऑरेंज और 18 में यलो अलर्ट जारी किया है। अगर बारिश होती है तो अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है।

### संक्षिप्त समाचार

## अमेरिकी संसद में ईरान जंग रोकने वाला प्रस्ताव पास

● ट्रम्प के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ वोटिंग की, राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार बाकी

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास हो गया है। वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। हालांकि 3 रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। यह प्रस्ताव 50-47 से



● ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर नया कंट्रोल सिस्टम बनाया- ईरान ने पार्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (जीएसए) बनाकर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए अनुमति अनिवार्य कर दी। ईरान ने कहा कि बिना परमिशन गुजरना अवैध माना जाएगा। ईरान ने साफ कहा कि यूरेनियम संवर्धन उसका अधिकार है और वह किसी दबाव में नहीं आएगा। राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने भी कहा कि बातचीत होगी, लेकिन ईरान झुकेंगा नहीं।

पास हुआ, हालांकि इसे कानून बनाने के लिए अभी कुछ और चरणों से गुजरना होगा। अगर यह प्रस्ताव कानून बनता है, तो ट्रम्प सरकार को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। अभी सीनेट में इस पर अंतिम वोटिंग होनी बाकी है। इसके बाद इसे रिपब्लिकन बहुमत वाली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि उसके बाद भी ट्रम्प इसके खिलाफ वीटो कर सकते हैं। फिर उस वीटो को रद्द करने के लिए सीनेट और हाउस दोनों में दो-तिहाई बहुमत चाहिए होगा, जो नहीं है।

## ऑनलाइन बिक्री का विरोध सड़क पर दवा व्यापारी

● देशभर में 15 लाख मेडिकल स्टोर बंद कर जताया विरोध

नई दिल्ली (एजेंसी)। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और बड़ी कंपनियों के कॉम्पटीशन के विरोध में बुधवार को देशभर के 15 लाख से ज्यादा मेडिकल स्टोर बंद रहे। ऑल इंडिया



● दवा दुकानदारों की 4 मांगें- बिना नियमों के चल रही ऑनलाइन दवाओं की बिक्री से मोहल्ले की छोटी दुकानों को नुकसान हो रहा है और लोगों की सेहत के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। इसे रोकना चाहिए। इस पूरे विवाद से जुड़े सरकार के दो नियम हैं। संगठन के मुताबिक इन नियमों की कमियों का फायदा उठाकर ही ऑनलाइन दवा कंपनियां ऐसा कर रही हैं। इसे वापस लिया जाए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गलत या नकली पदार्थों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए ई-फार्मसी के लिए नए सख्त नियम बनाए जाएं। लोकल दुकानदार ऑनलाइन के विरोध में हैं।

ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स ने एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया था। बंद का मामूली असर दिखा। पटना के एम्स के बाहर मरीज और उनके परिवार वाले दवाओं के लिए परेशान दिखे। वहीं, चंडीगढ़ के पीएनजी में इलाज कराने आए कर्मियों के एक परिवार को भी दवाई नहीं मिल सकी। उसने कहा, दवाई नहीं मिल रही है। हालांकि, एजेंसी ने कहा था कि बंद के दौरान भी अस्पतालों से जुड़े स्टोर खुले रहेंगे।

## उज्जैन के कालभैरव मंदिर में अब वीआईपी दर्शन व्यवस्था

500 रुपए देकर सीधे गर्भगृह तक पहुंच सकेंगे श्रद्धालु; मंदिर के बाहर मिलेगा टिकट

उज्जैन (नप्र)। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर के बाद अब श्री काल भैरव मंदिर में भी श्रद्धालुओं के लिए शीघ्र दर्शन व्यवस्था शुरू कर दी गई है। बुधवार से लागू हुई इस नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालु 500 रुपए का टिकट लेकर सीधे गर्भगृह से दर्शन कर सकेंगे। टिकट मंदिर परिसर के बाहर बने काउंटर से सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। विश्व प्रसिद्ध श्री कालभैरव मंदिर, जहां भगवान काल भैरव को मंदिर का भोग लगाया जाता है, वहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बढ़ती श्रद्धालु संख्या और सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को देखते हुए मंदिर में 125.17 करोड़ रुपए की लागत से कोरिडोर



और अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मंदिर प्रशासन के अनुसार, फिलहाल यह व्यवस्था ऑफलाइन शुरू की गई है, जिसे जल्द ही ऑनलाइन भी किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं को विशेष मार्ग से सीधे

गर्भगृह तक पहुंचकर दर्शन की सुविधा मिलेगी। ऐसे मिलेंगे शीघ्र दर्शन- काल भैरव मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए वीआईपी प्रोटोकॉल की सशुल्क दर्शन व्यवस्था के

साथ सामान्य श्रद्धालु अगर शीघ्र दर्शन करना चाहता है तो उन्हें मंदिर के बाहर लगे टिकट काउंटर से 500 रुपए का टिकट लेना होगा। इसके बाद श्रद्धालुओं को मंदिर के निर्गम द्वार से लगे हुए मार्ग से प्रवेश मिलेगा, यहां से श्रद्धालु सीधे मंदिर के गर्भगृह द्वार के गेट से एंटी लेकर सीधे गर्भगृह में दर्शन कर सकेंगे। सिर्फ ऑफलाइन व्यवस्था अभी- काल भैरव मंदिर में प्रशासक एलएन गर्ग ने बताया कि अभी शुरुआत में ऑफलाइन टिकट व्यवस्था की है। इसे जल्द ही ऑनलाइन कर दिया जाएगा। यहां आने वाले श्रद्धालु शीघ्र दर्शन के नाम पर कई बार ठगी का शिकार होते थे।

## देख ले दुनिया! चांद पर पहुंच गया 'सपेरो' का देश

अपनी कुंठा में मग्न यूरोप, अमी और जलाएगी भारत की तरक्की

नई दिल्ली (एजेंसी)। हां, हम सपेरो हैं! और हमारी इस स्वीकारोक्ति में कोई शर्म नहीं, बल्कि 21वीं सदी के नए वैश्विक यथार्थ का सबसे बड़ा व्यंग्य छिपा है। हम वाकई सपेरो हैं, क्योंकि आज जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी, युद्ध की विभीषिका और कूटनीतिक अस्थिरता के जहरीले फन के आगे खोफजदा है, तब नया भारत अपनी नीतियों की 'बीन' से इन सभी वैश्विक संकटों को काबू कर रहा है। हाल ही में नॉर्वे के एक अखबार ने भारतीय प्रधानमंत्री को एक सपेरो के रूप में दर्शाते हुए जो कार्टून छपा है, वह कोई रचनात्मक व्यंग्य नहीं है। यह दरअसल उस यूरोपीय और पश्चिमी मीडिया की हताशा का प्रकटीकरण है, जो 19वीं सदी के 'कोलोनियल हैंगओवर' से आज तक बाहर नहीं आ सका है।



● अंतरिक्ष से लेकर सिलिकॉन वैली तक- 'बीन' की नई धुन- आज का भारत उस औपनिवेशिक ढांचे को तोड़कर बहुत आगे निकल चुका है। नॉर्वे के अखबार या अन्य पश्चिमी मीडिया घरानों की यह कुंठा दरअसल भारत की वर्तमान सफलताओं को पचाने का सही परिणाम है। जिस देश को वे दशकों तक दान और दया का पात्र मानते थे, आज वह उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग ने पश्चिमी देशों के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई है। जिस एलीट स्पेस क्लब पर पश्चिमी देशों का एकाधिकार था, भारत ने अपने स्वदेशी ज्ञान और बेहद कम बजट में उसके दरवाजे तोड़ दिए। अपना देश मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहली ही कोशिश में पहुंच गया है।

## ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल का ट्रायल पूरा

● टैंक, हेलीकॉप्टर और दूसरे ड्रोन को बना सकेगी निशाना

डीआरडीओ ने स्वदेशी कंपनियों के साथ कर दिया कमाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन ने ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल का ट्रायल पूरा कर लिया है। इस मिसाइल का नाम यूएलपीजीएम-वी3 है। यह हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के टारगेट पर सटीक हमला कर सकती है। हवा में दुश्मन के हेलीकॉप्टर, ड्रोन और दूसरे हवाई टारगेट को मार गिरा सकती है। वहीं जमीन पर टैंक, सैन्य वाहन और बंकर को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, मिसाइल का परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुनूल स्थित टेस्ट रेंज में किया गया। इसमें इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जो लॉन्च और कमांड सिस्टम को कंट्रोल करता है।

● चलते-फिरते टारगेट को भी लॉक कर सकती है- यूएलपीजीएम-वी3 एक स्मार्ट प्रिंसिपल गाइडेड मिसाइल है। इसमें सटीक तकनीक लगी है, जिससे यह टारगेट को पहचानकर लॉक करती है और फिर सटीक हमला करती है। चलते हुए लक्ष्य को भी ट्रैक कर सकती है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इसे एटी-टैंक रोल के लिए भी तैयार किया गया है। साथ ही यह ड्रोन, हेलीकॉप्टर और दूसरे हवाई लक्ष्यों के खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती है।

## बिजली बिल वसूली में नहीं करें कोताही : ऊर्जा मंत्री श्री तोमर

ऊर्जा मंत्री ने की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के कार्यों की समीक्षा

भोपाल (नप्र)। कम्पनी की आय बढ़ाने के लिये आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें। बिजली बिलों की वसूली में कोताही नहीं करें, लेकिन शुरुआत बड़े उपभोक्ताओं से करें। आवश्यकता अनुसार कॉलोनियों में वसूली शिविर भी लायेंगे। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह निर्देश मंत्रालय में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिये। अच्छा कार्य करने वालों को मिले बेहतर पोस्टिंग- ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि खराब स्थानों पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों को बेहतर पोस्टिंग दें। इससे अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों में विद्युतीकरण के लिये कार्य-योजना बनायें। बैकलूम में बताया गया कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली बिल भुगतान में सुधार आया है। मध्य क्षेत्र में 10 लाख 60 हजार स्मार्ट मीटर लगाये जा चुके हैं। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि इस बात की सतत समीक्षा करें कि किस क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाये जा चुके हैं, वहीं बिजली बिलों के भुगतान की स्थिति में कितना सुधार हुआ है। ट्रांसफार्मर फेल्टोर की दर कम करें- ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ट्रांसफार्मर फेल्टोर की संख्या कम से कम करें। ट्रांसफार्मर फेल्टोर की जानकारी नहीं देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही भी करें।

## फाल्टा में किरकिरी, अब 43 प्रॉपर्टी की लिस्ट जारी

मुश्किल में फंसे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी केएमसी का नोटिस, प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जों का शिकंजा

कोलकाता (एजेंसी)। विधानसभा चुनाव में हर के बाद टीएमसी के नंबर-2 और टीएमसी के शासन के दौरान सबसे ताकतवर रहे अभिषेक बनर्जी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। फाल्टा उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोट डालें जाएंगे और मंगलवार को इस सीट से चुनाव लड़ रहे टीएमसी कैडिडेट जहांगीर खान ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। फाल्टा विधानसभा डायमंड हार्बर लोकसभा सीट का हिस्सा है, जहां से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। इससे पहले सोमवार



शाम को कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने अभिषेक बनर्जी के घर शांति निकेतन पर नोटिस चिपकाया है जिसमें 17 प्रॉपर्टी का जिक्र है।

● अभिषेक बनर्जी को फाल्टा में मिली थी 1.68 लाख की लीड- पहली बात फाल्टा उपचुनाव की। वोटिंग से पहले टीएमसी कैडिडेट जहांगीर खान के पैर खींचने से टीएमसी की ज्यादा किरकिरी हो रही है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी की धमकियों के कारण जहांगीर बैकफुट पर गए। फाल्टा विधानसभा सीट अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र में आता है। 2024 में अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर से सात लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। फाल्टा विधानसभा से उन्हें 1.68 लाख वोटों की लीड मिली थी।

# पुलिस को चकमा देकर भाग रहे तस्करो की गाड़ी भिड़ी, 1 करोड़ की ड्रग्स जब्त

इंदौर। शहर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच अंतरराज्यीय तस्करो को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से एक करोड़ रुपए कीमत की एक किलो से अधिक एमडी ड्रग, हथियार और वाहन जब्त किए गए। पुलिस से बचने के प्रयास में आरोपियों की स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में अनिर्वाहित होकर ड्रिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया। अपराध शाखा को सूचना मिली थी कि कुछ तस्करो भारी मात्रा में एमडी ड्रग लेकर इंदौर पहुंचने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने सुबह करीब 6 बजे सुपर कॉम्प्लेक्स स्थित टीसीएस चौराहे के पास निगरानी और घेराबंदी की। इस दौरान काले रंग की स्कॉर्पियो ब्रह्म पहुंची। पुलिस ने वाहन रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी वाहन लेकर भाग निकले। पीछा करने के दौरान कुछ दूरी पर स्कॉर्पियो अनिर्वाहित होकर ड्रिवाइडर से जा टकराई। इसके बाद

## पांच अंतरराज्यीय तस्करो गिरफ्तार, हथियार और वाहन भी बरामद



### इन्हें गिरफ्तार किया गया

पुलिस ने मामले में नवीन सोलंकी, गोविंद वर्मा, शंकर सिंह, विक्रम सिंह और नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कुछ आरोपी राजस्थान के झालावाड़ से जुड़े हैं, जबकि अन्य उज्जैन, देवास और इंदौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक किलो से अधिक एमडी मादक पदार्थ बरामद हुआ। इसके अलावा एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, स्कॉर्पियो वाहन और दो मोटरसाइकिल भी जब्त की गई हैं।

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को धर दबोचा।

### ड्रग तस्करी करने की बात स्वीकारी

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आरके सिंह ने बताया कि प्रदेशभर में मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की प्रार्थनिकता है कि नशे के कारोबार से जुड़े लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में अपराध शाखा को सूचना मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने कई महीनों से एमडी ड्रग तस्करी करने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद सामग्री कहाँ से लाई गई थी और इसकी आपूर्ति किन लोगों तक की जानी थी। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।



## इंदौर में बसों पर बड़ा एक्शन, आठ बसों से 2.26 लाख जुर्माना वसूला

### इमरजेंसी एग्जिट बंद मिले, दो बसों के फिटनेस निरस्त किए

इंदौर। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर मंगलवार को आरटीओ और जिला प्रशासन ने शहर में बसों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान विभिन्न नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 8 बसों से कुल 2 लाख 26 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया, जबकि दो बसों के फिटनेस प्रमाणपत्र निरस्त कर दिए गए। स्टार चौराहे पर हुई संयुक्त कार्रवाई में खासतौर पर ऑल इंडिया टूरिस्ट बसों की जांच की गई। टीम ने बसों में इमरजेंसी एग्जिट, फायर सेफ्टी सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर और आपातकालीन निकास व्यवस्था की स्थिति

परखी। जांच में कई बसों में इमरजेंसी एग्जिट बंद मिले और अग्निशमन उपकरण खराब हालत में पाए गए। इसके अलावा कुछ बसें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लेकर स्टैंडिंग कैरिज के रूप में संचालित होती मिलीं, जो परमिट शर्तों का उल्लंघन है।

दस्तावेज अपूर्ण मिलने पर भी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान आरटीओ प्रदीप शर्मा, एसडीएम वनश्याम धनगर, एआरटीओ राजेश गुप्ता और उड्डनदस्ता टीम प्रभारी आकाश सिटोले मौजूद रहे। अधिकारियों ने बस संचालकों और चालक-परिचालकों को यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जागरूक करते हुए इमरजेंसी एग्जिट और कांच तोड़ने वाले हैमर के उपयोग की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए।

### कलेक्टर शिवम वर्मा 'फेम इंडिया' सूची में



इंदौर। 'फेम इंडिया मैगजीन' और 'एशिया पोस्ट' द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' सर्वेक्षण के प्रारंभिक परिणाम जारी कर दिए गए। इसमें इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के साथ ही जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, सतना कलेक्टर सतीश

कुमार, नरसिंहपुर कलेक्टर रजनी सिंह और भोपाल कलेक्टर कोशलेंद्र सिंह हैं। सर्वे में देशभर के करीब 800 जिलों में कार्यरत जिलाधिकारियों और डिप्टी कमिश्नरों के कामकाज, प्रशासनिक क्षमता और जनसेवा से जुड़े कार्यों का मूल्यांकन किया गया। इसके बाद लगभग 100 अधिकारियों को प्रारंभिक सूची में शामिल किया गया है। 'फेम इंडिया' के अनुसार चयन प्रक्रिया में प्रशासनिक दक्षता, सुशासन, संकट प्रबंधन, नवाचार, जवाबदेही, विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन समेत 10 प्रमुख मानकों का आधार बनाया गया। इसके अलावा विशेषज्ञों की राय, ग्राउंड रिपोर्ट, मीडिया विश्लेषण और जनसरोकार से जुड़े पहलुओं को भी सर्वे का हिस्सा बनाया गया।

### बिजली कटौती पर दो इंजीनियरों को नोटिस

इंदौर। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सोमवार रात इंदौर के बिजली सब स्टेशनों का औचक निरीक्षण कर उपभोक्ताओं से सीधा संवाद किया। ओल्ड प्लासिया और मनोरामगंज क्षेत्र में बार-बार बिजली जाने की शिकायत मिलने पर मंत्री ने सख्त नाराजगी जताई। प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर बिजली विभाग के इंजीनियर सत्यप्रकाश जायसवाल और कमलेश टाले को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि बिजली आपूर्ति में लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेटेस कार्य गुणवत्तापूर्ण हो और इसकी पूर्व सूचना रहवासियों को दी जाए। मंगलवार दोपहर दोनों इंजीनियरों को नोटिस जारी कर दिए गए। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वेतनवृद्धि रोकने जैसी कार्रवाई भी की जाएगी।

### बच्चों ने दिया सड़क सुरक्षा का संदेश

इंदौर। शहर में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आरके सिंह और यातायात डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी मौजूद रहे। कार्यक्रम की सबसे खास प्रस्तुति अरुणाभ संस्था के स्पेशल बच्चों की रही। बच्चों ने आकर्षक ड्राइंग बनाकर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। चित्रों के माध्यम से शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग से बचने, रेड लाइट का पालन करने तथा हेल्मेट और सीट बेल्ट लगाने की सीख दी गई। पुलिस कमिश्नर ने बच्चों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए समाज में ऐसी जागरूकता बेहद जरूरी है। उन्होंने बच्चों से संवाद कर उनके सवालों के जवाब भी दिए। इस दौरान बच्चों ने यातायात पुलिस की ब्रीथ एनालाइजर मशीन, बॉडी वार्न कैमरे और अन्य उपकरणों की कार्यप्रणाली को करीब से समझा। अधिकारियों ने कहा कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए ऐसे जागरूकता अभियान लगातार चलाए जाएंगे।

### बस हादसों की वजह बीएस-6 तकनीक

इंदौर। मध्यप्रदेश बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने बीएस-6 तकनीक पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे यात्री बसों में आग लगने की बड़ी वजह बताया है। संगठन पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में हाल ही में हुए इंदौर-शिवपुरी बस आग कांड का उल्लेख करते हुए कहा कि हादसे के लिए बस चालक, परिचालक या मालिक जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि नई तकनीक में खामियां सामने आ रही हैं। एसोसिएशन का कहना है कि प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से लागू की गई बीएस-6 तकनीक अब यात्रियों की सुरक्षा पर भारी पड़ रही है। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि जिस स्थान पर बस में आग लगी, उसके पास टोल नाका होने के बावजूद एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी जरूरी आपात सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं, जिससे जनहानि हुई। बस ऑपरेटरों ने सरकार से बीएस-6 तकनीक की समीक्षा कर इसे बंद करना या वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी गई तो प्रदेशभर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

### बकरा खरीदने आए युवक का अपहरण

इंदौर। खजराना थाना क्षेत्र से अपहरण की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। चंदन नगर निवासी महफूज पिता जाकिर को बदमाशों ने उस समय अगवा कर लिया, जब वह खजराना इलाके में बकरा खरीदने पहुंचा था। आरोपियों ने युवक को कार में जबरन बठाया और सीहोर जिले के कालापीपल ले जाकर बंधक बना लिया। वहां उसकी बेरहमी से पिटाई की गई।

## अलग-अलग स्थानों पर आग का तांडव कार्यालय, गोदाम, वाहन जलकर राख

इंदौर। शहर में बुधवार और मंगलवार को अलग-अलग क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं से अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लसूडिया स्थित बेलमोर्ट पार्क के रखरखाव कार्यालय, खंडवा रोड की सब्जी दुकान और नायता मुंडला क्षेत्र के अवैध पटाखा गोदाम में लगी आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। राहत की बात यह रही कि सभी घटनाओं में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। लसूडिया क्षेत्र स्थित बेलमोर्ट पार्क के रखरखाव कार्यालय में बुधवार तड़के आग लग गई। यहां टाउनशिप निर्माता का कार्यालय भी संचालित होता है। अग्निशमन विभाग के सहायक उप निरीक्षक सुशील कुमार दुबे ने बताया कि सुबह करीब पांच बजे सुरक्षा गार्ड ने कार्यालय से धुआं उठते देखा। आसपास मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैल गई। सूचना मिलने पर दमकल दल मौके पर पहुंचा और पानी डालकर आग पर नियंत्रण पाया। घटना में कार्यालय का फर्नीचर, उपकरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।

### सब्जी की दुकान में आग - इसी तरह खंडवा रोड स्थित अनुराधा नगर में अलसुबह एक सब्जी दुकान में भी आग लग गई। दुकान संचालक बबली पति प्रीतम सिंह की दुकान में लगी आग ने कुछ ही देर में पूरा सामान अपनी चपेट में ले लिया। दमकल दल ने करीब एक हजार लीटर पानी डालकर आग बुझाई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।

### लसूडिया, खंडवा रोड और नायता मुंडला क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं



### पटाखा गोदाम में भीषण आग

नायता मुंडला क्षेत्र में मंगलवार शाम अवैध रूप से संचालित पायरो पटाखा गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कण मच गया। आग लगते ही पटाखों में लगातार विस्फोट होने लगे, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। पटाखों से निकली धिंगारियां पानी स्थित रंजीत सिंह के ऑयल गोदाम तक पहुंच गईं और आग तेजी से फैलते हुए ऊपर बनी व्यायामशाला तक जा पहुंची। घटना के समय व्यायामशाला में मौजूद पांच से छह युवक पीछे के रास्ते से बाहर निकलकर सुरक्षित बच गए। हादसे में एक आंटी, एक कार और पांच दोपहिया वाहन जलकर राख हो गए। अग्निशमन विभाग के उप निरीक्षक संतोष कुमार दुबे ने बताया कि शाम 5 बजकर 53 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद दो दमकल वाहन और दो पानी के टैंकर मौके पर भेजे गए। करीब 35 हजार लीटर पानी की मदद से लगभग दो घंटे की मशकत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

## रंगों से निखर रहा इंदौर, दीवारों दे रहीं शहर स्वच्छता का संदेश

### निगम की पहल से सड़कों और चौराहों पर कलात्मकता



इंदौर। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को और अधिक सुंदर एवं आकर्षक बनाने के लिए नगर पालिक निगम ने नई पहल शुरू की है। शहर की दीवारों, सार्वजनिक स्थलों और प्रमुख मार्गों पर आकर्षक पेंटिंग व कलात्मक चित्रकारी की जा रही है। रंग-बिरंगी कलाकृतियों से सजी ये दीवारें न केवल लोगों का ध्यान खींच रही हैं, बल्कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रही हैं। नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे चित्रों में स्वच्छ इंदौर, हरित वातावरण, जल संरक्षण और नागरिक जिम्मेदारी जैसे विषयों को प्रमुखता दी गई है। शहर के कई हिस्सों में कलाकारों ने स्थानीय संस्कृति और आधुनिक कला का सुंदर मिश्रण पेश किया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य शहर को सुंदर बनाने के साथ लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। नागरिकों ने भी इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि रंगों और रचनात्मकता से सजा इंदौर अब और अधिक आकर्षक दिखाई देने लगा है।

## 4 साल के संघर्ष के बाद किडनी का प्रत्यारोपण होगा, मां देगी किडनी

### प्रशासन से मिली सहायता के बाद ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू

इंदौर। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में कई लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इसी दौरान राम नगर निवासी शोभा संतोष घाई तड़क ने अपनी बेटी के इलाज और आर्थिक संकट की मार्मिक कहानी सुनाई। प्रशासन की ओर से मिली आर्थिक सहायता के बाद अब उनकी बेटी के किडनी प्रत्यारोपण की उम्मीद मजबूत हुई है। शोभा ने बताया कि उनकी 28 वर्षीय बेटी सोनिया पिछले चार वर्षों से गंभीर बीमारी से जूझ रही है। उसका इलाज एमवाय अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चल रहा है। इससे पहले मुंबई के केईएम अस्पताल में भी उपचार कराया गया, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के

कारण लगातार इलाज करना बेहद कठिन हो गया। बोते चार वर्षों से सोनिया का नियमित डायलिसिस हो रहा है। उन्होंने कहा कि परिवार में कोई सहारा नहीं है और इलाज से लेकर घर खर्च तक की जिम्मेदारी अकेले उठनी पड़ रही है। दवाइयों, भोजन, अस्पताल आने-जाने और अन्य खर्चों के लिए उन्हें लोगों से मदद मांगनी पड़ी। कई बार वे दुकान-दुकान जाकर सहायता मांगती रहीं और छोटी-छोटी रकम जुटकर बेटी का इलाज जारी रखा।

**रक्त समूह की दिक्कत** - शोभा ने बताया कि शुरुआत में किडनी प्रत्यारोपण कराने की स्थिति नहीं

## हॉस्टल में उत्पात के बाद छात्रों ने हाथ जोड़े, 'भविष्य बचाने का अवसर दें!'

### तोड़फोड़ मामले में डीएवीवी सख्त, रिजल्ट रोकने, जुर्माने की तैयारी



जाएगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई नियमों के अनुसार ही होगी।

### दो घंटे तक उत्पात मचाया

कुछ दिन पहले रामानुज छात्रावास में करीब दो घंटे तक छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया था। इस दौरान टेबल-कुर्सियां, पानी ठंडा करने की मशीन, पानी की टैंकियां और खिड़कियों के कांच तोड़ दिए गए थे। घटना के

दौरान कुछ छात्रों के नशे में होने की बात भी सामने आई थी। मामले में अब छात्रों के अभिभावकों को इंदौर बुलाकर परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे। वहीं छात्रावास में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग के आधार पर मुख्य आरोपियों की पहचान की जा रही है।

### अंतिम निर्णय कुलपति स्तर पर

आईईटी निदेशक प्रो प्रतोप बंसल ने कहा कि छात्रों ने वीडियो जारी कर अपनी गलती स्वीकार की है, लेकिन नुकसान की भरपाई उन्हें करनी ही पड़ेगी। मामले में अंतिम निर्णय कुलपति स्तर पर लिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन हंगामे में शामिल छात्रों का परीक्षा परिणाम रोकने की तैयारी कर रहा है। साथ ही प्रत्येक छात्र पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाने और जिन कंपनियों में उनका परिसर चयन हुआ है, वहीं घटना की जानकारी भेजने पर भी विचार किया जा रहा है।

**तत्काल 2 लाख की मदद** - एक सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें कलेक्टर कार्यालय लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी स्थिति प्रशासन के सामने रखी। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने तत्काल दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। इसमें एक लाख रुपए प्रशासन की ओर से और एक लाख रुपए उनकी टीम के सहयोग से दिए गए। शोभा ने बताया कि प्रशासन ने यह भरसा भी दिलाया है कि जयपुर में ऑपरेशन के बाद रहने और अन्य जरूरतों में भी सहायता की जाएगी।

जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में संपर्क किया गया, जहां लगभग सात लाख रुपए खर्च बताया गया।



## संकल्प

गौरव अस्वस्थी



ओ डिशा-छतीसगढ़ सीमा के जंगलों के बीच बसे बरगढ़ जिले के अंतिम गांव कूदोपाली में शिक्षा की एक ऐसी कहानी आकार ले रही है, जिसे आधुनिक समय का 'नया शांतिनिकेतन' कहा जा सकता है। यह कहानी केवल एक स्कूल की नहीं, बल्कि उस संकल्प की है जिसमें एक लोककवि ने अपने संघर्षों से उपजी संवेदना को गरीब, अनाथ और आदिवासी बच्चों के भविष्य से जोड़ दिया।

कोसली भाषा के प्रसिद्ध लोककवि और पद्मश्री सम्मान से अलंकृत हलधर नाग ने यहां 'पद्मश्री लोककवि हलधर नाग आवासीय वन विद्यालय' की स्थापना की है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने जिस तरह प्रकृति की गोद में शांतिनिकेतन बसाया था, उसी तरह हलधर नाग ने गांव की डूरी यानी पथरीली जमीन पर शिक्षा का यह आश्रम खड़ा किया। जंगलों के बीच खड़ी यह इमारतें आज उन बच्चों के सपनों का आधार बन चुकी हैं, जिनके लिए कभी शिक्षा एक दूर की चीज थी।

बरगढ़ जिले के घेंस गांव में जन्मे हलधर नाग का जीवन स्वयं संघर्षों से भरा रहा है। बेहद साधारण परिवार में जन्मे नागजी ने गरीबी को बहुत करीब से देखा। परिवार चलाने के लिए उन्होंने स्कूल में रसोइए का काम किया, स्टेशनरी की छोटी दुकान चलाई और कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताया। पांचवीं कक्षा तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वाले इस लोककवि ने अपनी प्रतिभा और संवेदनशीलता के बल पर साहित्य जगत में अलग पहचान बनाई। उनकी पहली कविता 'ढाड़ो बरगछ' यानी 'बूढ़ा बरगद' थी। प्रकृति, लोकजीवन और मानवीय संवेदनाओं पर केंद्रित उनकी कविताओं ने उन्हें पश्चिमी ओडिशा की सांस्कृतिक पहचान बना दिया।

हलधर नाग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्हें अपनी समस्त कविताएं और महाकाव्य कंठस्थ हैं। उन्होंने 22 से अधिक महाकाव्य और खंडकाव्य रचे हैं, जिनका हिंदी, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। उस समय उनकी सादगी और अभावों से भरे जीवन की चर्चा पूरे देश में हुई थी। कहा जाता है कि दिल्ली जाकर सम्मान ग्रहण करने के लिए उन्होंने प्रारंभ में यह कहकर असमर्थता जताई थी कि उनके पास यात्रा का खर्च नहीं है।

लेकिन जीवनभर अभावों से जूझने वाले इसी लोककवि ने यह तय किया कि आर्थिक तंगी किसी बच्चे की पढ़ाई में बाधा नहीं बनने देंगे। इसी संकल्प से

# कूदोपाली : पथरीली जमीन पर 'शिक्षा के फूल'

हलधर नाग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्हें अपनी समस्त कविताएं और महाकाव्य कंठस्थ हैं। उन्होंने 22 से अधिक महाकाव्य और खंडकाव्य रचे हैं, जिनका हिंदी, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। उस समय उनकी सादगी और अभावों से भरे जीवन की चर्चा पूरे देश में हुई थी। कहा जाता है कि दिल्ली जाकर सम्मान ग्रहण करने के लिए उन्होंने प्रारंभ में यह कहकर असमर्थता जताई थी कि उनके पास यात्रा का खर्च नहीं है। लेकिन जीवनभर अभावों से जूझने वाले इसी लोककवि ने यह तय किया कि आर्थिक तंगी किसी बच्चे की पढ़ाई में बाधा नहीं बनने देंगे। इसी संकल्प से वर्ष 2009 में कूदोपाली गांव में 'पद्मश्री लोककवि हलधर नाग आवासीय वन विद्यालय' की शुरुआत हुई। शुरुआत बेहद साधारण थी। स्कूल के नाम पर केवल घास-फूस की मड़ैया थी और छात्र संख्या महज 17।

वर्ष 2009 में कूदोपाली गांव में 'पद्मश्री लोककवि हलधर नाग आवासीय वन विद्यालय' की शुरुआत हुई। शुरुआत बेहद साधारण थी। स्कूल के नाम पर केवल घास-फूस की मड़ैया थी और छात्र संख्या महज 17।

विद्यालय की स्थापना में गांव के महेंद्र कुमार ने ढाई एकड़ जमीन दान में दी। उनके बेटे जनक कुमार ने विद्यालय की देखरेख का दायित्व अपने ऊपर लिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों की सेवा को समर्पित कर दिया। विवाह न करने के सवाल पर जनक कुमार सहजता से कहते हैं- 'ये सारे बच्चे ही हमारे परिवार हैं।'

आज यह विद्यालय 125 से अधिक बच्चों की शिक्षा का केंद्र बन चुका है। यहां पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे गरीब, अनाथ और आदिवासी परिवारों से आते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता-पिता मजदूरी करते हैं या जिनके परिवार शिक्षा का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं। जंगलों के बीच स्थित यह विद्यालय उनके लिए आशा का केंद्र बन गया है।

विद्यालय की एक और बड़ी विशेषता यह है कि यहां शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है। बच्चों को श्रम, अनुशासन, सेवा और सामूहिक जीवन का संस्कार भी दिया जाता है। अवकाश के दिनों में बच्चों ने स्वयं श्रमदान कर खेल मैदान समतल किया। वे विद्यालय परिसर में सब्जियां और अन्य फसलें उगाते हैं भी सहयोग करते हैं। मध्याह्न भोजन तैयार करने और परीसने में भी बच्चे सहभागी बनते हैं।

भ्रमण के दौरान विद्यालय में अवकाश था, लेकिन 10-12 बच्चे छुट्टियों में भी वहीं रहकर पढ़ाई कर रहे थे। कोई सेना में जाना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है और कोई बैंक मैनेजर। बच्चों की आंखों में

विद्यालय की सबसे बड़ी ताकत है।

समय के साथ इस विद्यालय को समाज का सहयोग भी मिलने लगा। हलधर नाग विभिन्न आयोजनों में मिलने वाली सम्मान राशि और अपनी पुस्तकों की रॉयल्टी का अधिकांश हिस्सा विद्यालय पर खर्च करते हैं। पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद कई संस्थाएं, समाजसेवी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी इस प्रयास से जुड़ गईं।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने बच्चों के लिए छात्रावास निर्माण में सहयोग दिया। राज्यसभा सदस्य निरंजन बीसी ने अपनी सांसद निधि से पानी की टंकी, सोलर लाइट, बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कराई। ग्राम पंचायत ने बाउंड्रीवाल बनवाकर जंगली जानवरों के खतरों को कम किया।

विद्यालय परिसर में अब पक्के कक्ष बन चुके हैं और कुछ नए कक्ष निर्माणाधीन हैं। बरामतों की दीवारों पर देश और ओडिशा के महानुरोहों के चित्र लगे हैं, जो बच्चों को प्रेरित करते हैं। हालांकि विद्यालय परिसर भी दिखाई देती है। विद्यालय की रसोई में भोजन अब भी जंगल से लाई गई लकड़ियों के चूल्हे पर पकता है। जनक कुमार बताते हैं कि गैस पर भोजन बनाना विद्यालय के लिए महंगा पड़ता है। विद्यालय के पूर्व छात्र आज उच्च शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। मजदूर पिता की आदिवासी बेटे मिली भोई, जिसने बचपन में ही मां को खो दिया था, आज

भुवनेश्वर के प्रतिष्ठित कोर्टस संस्थान से बीटेक कर रही है। इसी विद्यालय के छात्र मोहन बरिहा बीबीए की पढ़ाई कर रहे हैं। यह बदलाव बताता है कि जंगलों के बीच शुरू हुई यह छोटी पहल अब बच्चों के जीवन में बड़े परिवर्तन का माध्यम बन रही है।

विद्यालय को प्रवासी ऑडिया परिवारों और स्थानीय समाज का भी सहयोग मिल रहा है। अमेरिका में रह रहे बालकृष्ण दीक्षित और उनका परिवार विद्यालय के निर्माण और मासिक खर्च में मदद कर रहा है। छतीसगढ़ के जशपुर जिले के सेवानिवृत्त शिक्षक लक्ष्मण साहू ने भी यहां कक्ष निर्माण में सहयोग दिया है। आसपास के ग्रामीण मध्याह्न भोजन के लिए अपनी फसल दान में दे जाते हैं।

हलधर नाग जब बच्चों के बीच पहुंचते हैं तो पूरा वातावरण जीवंत हो उठता है। बच्चे उन्हें घर लेते हैं और उनकी प्रिय कविता 'ई माटी पावन पोरे' सामूहिक स्वर में गाने लगते हैं। कुछ देर के लिए पूरा परिसर साहित्यिक और भावनात्मक ऊर्जा से भर जाता है। लोककवि बच्चों को कविता सुनाने के साथ-साथ अच्छे इंसान बनने की सीख भी देते हैं।

कूदोपाली का यह वन विद्यालय बताता है कि शिक्षा केवल भवनों और संसाधनों से नहीं चलती, बल्कि संवेदना, समर्पण और सामाजिक सहभागिता से जीवित रहती है। पथरीली जमीन पर उगे ये 'शिक्षा के फूल' इस बात का प्रमाण हैं कि यदि संकल्प मजबूत हो तो जंगलों के बीच भी सपनों की खेती की जा सकती है।

आज जब शिक्षा तेजी से बाजार और प्रतिस्पर्धा के दबाव में बदल रही है, तब कूदोपाली का यह 'नया शांतिनिकेतन' याद दिलाता है कि शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य मनुष्य बनाना है। हलधर नाग का यह प्रयास केवल विद्यालय निर्माण नहीं, बल्कि समाज के सबसे वंचित बच्चों के भविष्य को रोशन करने का आंदोलन है।

## सामयिक

राज कुमार सिन्हा

लेखक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं।



एक अध्ययन के अनुसार, ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी इस समय प्रतिदिन 1.9 डिग्री गर्म होने की ओर है जो पेरिस समझौते के लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल से जुड़े जलवायु वैज्ञानिकों की एक टीम ने शोध-पत्र में उल्लेख किया गया है कि भारत का औसत तापमान पिछले एक दशक (2015-2024) में लगभग 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, जो 20वीं सदी की शुरुआत (1901-1930) की तुलना में अधिक है। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी और पूर्वोत्तर भारत में वर्ष के सबसे गर्म दिन का तापमान 1950 के दशक से अब तक 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है।

बढ़ती गर्मी और लगातार पड़ रही हीटवेव के कारण शहर के निवासियों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है, जिसका सबसे अधिक असर श्रमिकों और कमजोर समुदायों पर पड़ रहा है। दुनिया की 100 सबसे गर्म शहरों की सूची में 95 नाम भारत के शहर का है। शहर में लगातार हो रहे निर्माण कार्यों और जंगलों की कटाई के कारण प्राकृतिक ठंडक

## अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर विशेष

श्वेता गोयल

लेखक शिक्षक हैं।



चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, यह एक संस्कृति है, एक संवाद है और दुनिया के करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार है। दुनियाभर में पानी के बाद यदि कोई पेय पदार्थ सबसे ज्यादा पसंद और उपभोग किया जाता है तो वह है चाय। सुबह की पहली किरण के साथ नॉद को अलविदा कहने से लेकर, दफ्तर की थकान मिटाने और मेहमानों के स्वागत तक, चाय हमारे जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा बन चुकी है। इसी महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल 21 मई को 'अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस' मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम 'चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना' न केवल चाय के पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन पर जोर देती है बल्कि उन लाखों छोटे किसानों और श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने का भी आह्वान करती है, जिनकी आजीविका इस उद्योग से जुड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का इतिहास बेहद दिलचस्प है। कुछ साल पहले तक दुनियाभर के चाय उत्पादक देशों में यह दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता था। इसकी शुरुआत सबसे पहले वर्ष 2005 में भारत की राजधानी नई दिल्ली से हुई थी। इसके बाद श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और केन्या जैसे देशों ने मिलकर इसे मनाया शुरू किया। हालांकि, तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं थी। चाय को वैश्विक मंच पर उसका वास्तविक हक दिलाने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ी और दूरदर्शी पहल की। वर्ष 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। भारत के प्रस्ताव पर गहन विचार करने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2019 को एक संकल्प

## भारत के शहर क्यों बन रहे हैं आग के गोले?

गायब हो गई है। शहर के तालाबों को बिल्डर भरकर मकान बना कर बेच रहे हैं। शहरों में कॉन्क्रीट और डामर की सड़कें दिन भर गर्मी सोखती हैं और रात में छोड़ती हैं, जिससे शहर गांवों की तुलना में ज्यादा गर्म रहते हैं। वाहनों, उद्योगों और एयर कंडीशनर (एसी) के अत्यधिक उपयोग से भारी मात्रा में कृत्रिम गर्मी निकलती है, जो शहरों के तापमान को बढ़ाती है। राजधानी भोपाल में ग्रीन कवर घटने की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट व आईआईएससी बेंगलुरु के रिपोर्ट के अनुसार 2009 में 35 प्रतिशत क्षेत्र में जंगल था। जो 2019 में महज 9 प्रतिशत रह गया। 2030 तक 3 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है।

हमलोग पेड़ काटकर ढाड़ें बनाने और जंगल उखाड़कर खदानें खोलने में लगे हैं, तो नतीजे आज हम भुगत रहे हैं। भारत आज एक 'हीट चैंबर' बन चुका है, और इसकी जवाबदेही मौसम पर खलकर जिम्मेदार बन निकलते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार, भारत चरम मौसम घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के मामले में पांचवां सबसे अधिक संवेदनशील देश है। एक वैश्विक समीक्षा 2017 में कहा गया है कि यदि वैश्विक तापमान में वृद्धि का वर्तमान रज्जान जारी रहता है, तो सदी के अंत तक गर्मी और आर्द्रता के बढ़ते स्तर के कारण

प्रशांत महासागर में विकसित होने वाली जलवायु घटना अल नीनो के कारण वैश्विक तापमान सामान्य से अधिक बढ़ गया है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में बनने वाले अल नीनो वैश्विक तापमान को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा सकता है। पहले अल नीनो एक प्राकृतिक चक्र था, लेकिन अब मानवजनित जलवायु परिवर्तन इसकी तीव्रता बढ़ा रहा है। समुद्र लगातार गर्म हो रहे हैं और चरम मौसम की घटनाएँ बढ़ रही हैं। हीटवेव बढ़ने का सबसे बड़ा कारण वैश्विक गर्मी है। जब हम कोयला, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वातावरण में जाती हैं। ये गैसों गर्मी को बाहर जाने से रोकती हैं, जिससे धरती का तापमान बढ़ता है। भारत में पिछले चार दशकों में लू की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ी है, जिससे कई क्षेत्रों में गर्मी का प्रभाव अधिक हुआ।

मध्यप्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन क्रियान्वयन योजना 2023-28 तैयार की है, जिसमें 97,000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। लेकिन पर्यावरण विभाग का बजट मात्र 31 करोड़ रुपये है।

जबकि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट बताती है कि जनवरी 2022 से 2025 तक मध्यप्रदेश ने 598 दिनों में गंभीर मौसम का सामना किया है और इस दौरान 1,439 लोगों की मौतें हुई हैं। सरकार जलवायु संकट की गंभीरता को प्राथमिकता नहीं दे रही है। जबकि पूरी दुनिया जलवायु संकट से निपटने के लिए निवेश बढ़ रही है, तब मध्यप्रदेश सरकार को ठोस कार्ययोजना बनाने का प्रयास करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य का नहीं, बल्कि वर्तमान का सबसे बड़ा मानवीय संकट बन चुका है। भारत के शहर तेजी से 'हीट चैंबर' में बदल रहे हैं, जहां कॉन्क्रीट, अंधाधुंध निर्माण, जंगलों की कटाई, तालाबों के विनाश और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर विकास मॉडल ने

प्राकृतिक संतुलन को गंभीर रूप से बिगाड़ दिया है। इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीबों, श्रमिकों, बुजुर्गों और कमजोर समुदायों पर पड़ रहा है, जिनके पास बढ़ती गर्मी से बचने के संसाधन नहीं हैं। भोपाल जैसे शहरों में घटता ग्रीन कवर और बढ़ते तापमान इस बात का संकेत हैं कि यदि विकास की वर्तमान दिशा नहीं बदली गई, तो आने वाले वर्षों में जीवन और आजीविका दोनों पर गंभीर खतरा पैदा होगा। सरकारें जलवायु संकट को केवल मौसम की असामान्य घटना बताकर अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकतीं। जब वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले दशकों में अत्यधिक गर्मी मानव जीवन के लिए असहनीय हो सकती है, तब केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है; उनके लिए ठोस बजट, राजनीतिक इच्छाशक्ति और जनभागीदारी आवश्यक है। आज जरूरत है कि विकास की परिभाषा को बदला जाए, पेड़ों, जलाशयों, जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों को बचाए बिना कोई भी विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। यदि अभी भी सरकारें, उद्योग और समाज नहीं चेंते, तो आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसे भारत का सामना करना पड़ेगा, जहां गर्मी केवल असुविधा नहीं बल्कि अस्तित्व का संकट बन जाएगा।

## सिर्फ पेय नहीं, दुनिया की धड़कन है चाय

प्रस्ताव पारित किया और 21 मई को आधिकारिक रूप से 'अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस' घोषित कर दिया। तब से लेकर आज तक, हर साल 21 मई को यह दिवस वैश्विक स्तर पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ मनाया जाता है। मई का महीना इसलिए भी चुना गया क्योंकि इस समय अधिकांश प्रमुख चाय उत्पादक देशों में उत्तम गुणवत्ता वाली चाय की फसल तैयार होती है। चाय की खेती बहुत ही विशिष्ट कृषि-पारिस्थितिक परिस्थितियों में होती है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में उतार-चढ़ाव और अनिश्चित वर्षा ने चाय बागानों को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऐसे में 'चाय को बनाए रखना' का अर्थ है, पर्यावरण-अनुकूल खेती यानी कीटनाशकों के सीमित उपयोग और जैविक खेती को बढ़ावा देना, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा यानी मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना और जल संरक्षण तकनीकों को अपनाया तथा पारदर्शी मूल्य श्रृंखला यानी खेत से लेकर कप तक एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाना, जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। चाय क्षेत्रवैश्विक स्तर पर अरबों डॉलर का उद्योग है लेकिन इसकी रीढ़ की हड्डी वे छोटे किसान

हैं। जो दिन-रात बागानों में पसीना बहाने का निर्गत खाद्य आयात बिलों के वित्तपोषण में मदद करता है, जिससे वह की अर्थव्यवस्थाओं को सहारा मिलता है। चाय का विकासशील और सबसे कम विकसित देशों में चाय का निर्यात खाद्य आयात बिलों के वित्तपोषण में मदद करता है, जिससे वह की अर्थव्यवस्थाओं को सहारा मिलता है। चाय का

इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति प्राचीन चीन में हुई थी, जहां इसका उपयोग शुरू में एक औषधीय पेय के रूप में किया जाता था। धीरे-धीरे यह चीन की सीमाओं को पार कर जापान, यूरोप और फिर औपनिवेशिक काल में भारत और दुनिया के अन्य कोनों तक पहुंची। आज, इतनी



सहस्राब्दियों के बाद भी स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक-आर्थिक विकास में इसका योगदान उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है। यदि वैश्विक स्तर पर चाय के आंकड़ों पर नजर डालें, तो परिदृश्य अत्यंत रोचक है।

दुनिया में सबसे अधिक चाय उत्पादन चीन में होता है जबकि भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एशिया महाद्वीप आज भी विश्व चाय उत्पादन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। उपभोग के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है, जहां चाय केवल पेय नहीं बल्कि सामाजिक संस्कृति का हिस्सा है। वैश्विक स्तर पर उत्पादित कुल चाय का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा उन्हीं देशों में उपभोग कर लिया जाता है, जहां इसका उत्पादन होता है। चाय उद्योग से 13 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है, जिनमें छोटे किसान और उनके परिवार प्रमुख हैं। भारत में उत्पादित चाय का लगभग 30 प्रतिशत घरेलू बाजार में ही खप जाता है। यहां चाय हर सुबह की ऊर्जा, रिश्तों की गर्माहट और जीवन के हर सुख-दुख की स्थायी साथी मानी जाती है। भारतीयों और चाय का रिश्ता अनुग्रह है। कुछ लोग इसे महज एक लत कह सकते हैं लेकिन देश के अधिकांश हिस्सों में यह 'जिंदगी की खुराक' और आतिथ्य का सबसे बड़ा प्रतीक है। यानी का बंगला हो या गरीब की झोपड़ी, घर आए मेहमान का स्वागत बिना चाय के अधूरा माना जाता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों (जैसे असम और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र) में विस्तृत चाय के बागान न केवल देश की अर्थव्यवस्था

पर उत्पादित कुल चाय का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा उन्हीं देशों में उपभोग कर लिया जाता है, जहां इसका उत्पादन होता है। चाय उद्योग से 13 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है, जिनमें छोटे किसान और उनके परिवार प्रमुख हैं। भारत में उत्पादित चाय का लगभग 30 प्रतिशत घरेलू बाजार में ही खप जाता है। यहां चाय हर सुबह की ऊर्जा, रिश्तों की गर्माहट और जीवन के हर सुख-दुख की स्थायी साथी मानी जाती है। भारतीयों और चाय का रिश्ता अनुग्रह है। कुछ लोग इसे महज एक लत कह सकते हैं लेकिन देश के अधिकांश हिस्सों में यह 'जिंदगी की खुराक' और आतिथ्य का सबसे बड़ा प्रतीक है। यानी का बंगला हो या गरीब की झोपड़ी, घर आए मेहमान का स्वागत बिना चाय के अधूरा माना जाता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों (जैसे असम और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र) में विस्तृत चाय के बागान न केवल देश की अर्थव्यवस्था

को गति देते हैं बल्कि लाखों परिवारों के जीवन का आधार भी है। चाय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हर व्यक्ति के स्वाद और मिजाज के अनुरूप खुद को ढाल लेती है। भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में इसे

बनाने के तरीकों में गजब की भिन्नताएँ हैं। दूध, चीनी और चायपत्ती को पानी के साथ अच्छी तरह उबालकर, उसमें अदरक, इलाइची, लौंग और काली मिर्च डालकर बनाई जाने वाली कड़क चाय अधिकांश भारतीयों की पहली पसंद है। कोरोना महामारी के दौर के बाद से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। जो लोग पहले चाय नहीं पीते थे, वे भी अब काढ़े या इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में अदरक और मसालों वाली चाय का सेवन करने लगे हैं। वजन नियंत्रित रखने और एंटीऑक्सीडेंट्स का लाभ उठाने के लिए आधुनिक जीवनशैली में ग्रीन टी और ब्लैक टी का चलन तेजी से बढ़ा है।

चाय दुनिया का सबसे पुराना और पानी के बाद सबसे अधिक पिया जाने वाला पेय पदार्थ है। जब हम अपने कप से चाय की एक चुस्की लेते हैं तो उसके पीछे किसी चाय बागान मजदूर के हाथों की मेहनत, किसी छोटे किसान की उम्मीदें और प्रकृति का अनमोल योगदान छुपा होता है। ब्रिटेन में 'आफ्टरनून टी', जापान में 'टी सेरमनी' और भारत में 'टपरी' की चाय' इसके गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाती है। सभी प्रकार की चाय (ब्लैक, ग्रीन, ओलॉंग, व्हाइट) मुख्य रूप से एक ही पौधे कैमेलिया साइनेंसिस से आती हैं। इनका स्वाद और रंग इनके ऑक्सीकरण और किण्वन की तकनीक के आधार पर बदल जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा दुनिया के छह चाय खेती स्थलों को 'विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली' घोषित किया गया है। इनमें से 4 चीन में, 1 जापान में और 1 दक्षिण कोरिया में स्थित है। प्रमुख उत्पादक देशों में कुल खपत अधिक होने के बावजूद प्रतिव्यक्ति खपत अभी भी कई पश्चिमी देशों की तुलना में कम है, जो यह दर्शाता है कि इस उद्योग में आगे बढ़ने की अभी अपार संभावनाएँ हैं।

## भविष्य मालिका पुराण अत्यंत गुप्त ग्रंथ, पंडित डॉ. काशीनाथ मिश्र उड़ीसा

भोपाल। जगन्नाथ संस्कृति के विशारद विद्वान पंडित डॉ.काशीनाथ मिश्र ने भगवान् के नित्य पंच सखा में से एक सखाअच्युतानंद द्वारा 6 सौ साल पूर्व रचित अत्यंत गुप्त ग्रंथ भविष्य मालिका पुराण के अंशों के आधार पर 2032 से सत्य युग की शुरुआत होने का दावा अपनी भविष्य मालिका पुराण पार्ट एक के अंश में लिखा है कि जब विद्वान और आध्यात्मिक दोनों महापरिवर्तन के आगमन को महसूस कर रहे होते हैं, तब भी मानवता के पास इस संकट से उबरने का कोई निश्चित और सार्वभौमिक समाधान नहीं होता। ऐसे समय में केवल 'भविष्य मालिका' ही दिव्या मार्ग प्रदान करती है, जो संपूर्ण मानव सभ्यता की रक्षा करने में सक्षम है। इस शास्त्र का मूल सिद्धांत है पापपूर्ण कर्मों का त्याग करें, और जीवन की रक्षा हेतु सभी धर्म के लोगों को 'त्रिकाल संध्या धारा' ( त्रिसंध्या संध्या ) को अपना चाहिए। जीवन में सत्य, शांति, दया, क्षमा और मित्रता जैसे गुणों को अपनाएं। युग परिवर्तन के इस समय में जीवन की रक्षा के लिए यह युग तत्व ही एकमात्र मृत्यु संजीवनी है। ज्ञातव्य है कि आपने 'श्री जगन्नाथ चेतना एवं संस्कृति जागरण' संस्थान के अध्यक्ष से वे निरंतर कथा व अनुष्ठान करते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश (कांगड़ा) : कांगड़ा के प्रागपुर (ज्वाला जी, वेदव्यास परिसर) में भव्य पंच-रात्रि जगन्नाथ अनुष्ठान का आयोजन एवं नेतृत्व किया था। वहीं राजस्थान (उदयपुर): उदयपुर की पावन भूमि पर उन्होंने अत्यधिक प्रचंड तापमान (40एसी से अधिक) के बीच भव्य दिव्य कल्मि कथा का सफल आयोजन किया था। वैश्विक (अंतरराष्ट्रीय) प्रचार एवं डिजिटल माध्यम से भविष्य मालिका एवं जगन्नाथ संस्कृति की कथाएं भौगोलिक सीमाओं को पार कर करके वैश्विक (ग्लोबल) स्तर पर पहुंच चुकी हैं। आप अंतरराष्ट्रीय संगठन भविष्य मालिका इंटरनेशनल (विश्व सनातन धर्म) संगठन की स्थापना की है। जिसके माध्यम से विश्वभर के साधक डॉ. काशीनाथ मिश्र जी उड़ीसा से जुड़े हुए हैं। वैश्विक डिजिटल सत्यंग: वे गूगल मीट और डिजिटल प्लेटफॉर्मस के माध्यम से देश-विदेश के भक्तों के लिए लाइव ऑनलाइन सत्यंग एवं कथा सत्रों का संचालन करते हैं।

भविष्य मालिका एवं जगन्नाथ संस्कृति की कथाएं भौगोलिक सीमाओं को पार कर वैश्विक ग्लोबल स्तर तक पहुंच चुकी हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन भविष्य मालिका इंटरनेशनल (विश्व सनातन धर्म) संगठन की स्थापना की है। जिसके माध्यम से विश्वभर 1सौ 56 देशों के साधक जुड़े हुए हैं। आप गूगल मीट एवं डिजिटल प्लेटफॉर्मस के माध्यम से देश-विदेश के भक्तों के लिए लाइव ऑनलाइन सत्यंग और कथा सत्रों का संचालन करते हैं। बहुभाषी अनुवाद और प्रसार: जगन्नाथ मलिका और भविष्य मालिका के ज्ञान को विश्वभर में पहुंचाने के लिए उनकी पुस्तकों (जैसे च्जगन्नाथ सौरभ संभारज) का अनुवाद हिंदी, ओड़िया, बांग्ला के साथ-साथ अंग्रेजी, रूसी (रशियन), जापानी भाषा में है।

## प्रकाश तरण पुष्कर में बच्चों की तबीयत बिगड़ी

### भोपाल में स्विमिंग के दौरान सांस लेने में तकलीफ; अस्पताल लेकर दौड़े परिजन

भोपाल (भा।)। भोपाल के लिंक रोड नंबर-1 स्थित प्रकाश तरण पुष्कर में स्विमिंग के दौरान करीब 4 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। परिजन बच्चों को तुरंत जेपी हॉस्पिटल लेकर



पहुंचे। स्विमिंग के दौरान 2 बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हालांकि, अब बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।

मामला बुधवार शाम 5 बजे का है। प्रकाश तरण पुष्कर में कई बच्चे स्विमिंग कर रहे थे। तभी उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन सचिन जैन ने बताया कि उनकी बेटी आध्या जैन (15) भी प्रकाश तरण पुष्कर गई हुई थीं। यहां करीब 20-25 बच्चे थे। जो बच्चे पानी में थे, उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी बेटी आध्या समेत दो बच्चों को तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। जहां सभी प्राथमिक इलाज किया गया।

## सेल्टिया हत्याकांड का इनामी आरोपी पुणे से गिरफ्तार

### युवक की हत्या कर शव तालाब में फेंका था, सभी आरोपी गिरफ्तार

बैतूल। बोरदेही थाना क्षेत्र में हुए वंचित सेल्टिया जलाशय हत्याकांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। मामले में फरार चल रहे 10 हजार रुपये के इनामी आरोपी को पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस सनसनीखेज हत्याकांड के सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। गौरतलब है कि 15 मई 2026 को ग्राम कारोपानी के समीप सेल्टिया जलाशय में एक युवक का शव सड़िध हालत में मिला था। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी राधेश्याम बट्टी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। युवक का शव पानी में औंधे मुंह पड़ा मिला था, जिसे एक भारी पेड़ के तने के नीचे दबाया गया था। मृतक की पहचान राजू उर्डके 22 निवासी ढाकरवाड़ी थाना नवेगांव जिला छिंदवाड़ा के रूप में हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने और गंभीर चोटों के कारण हत्या की पुष्टि हुई थी। जांच में सामने आया था कि मजदूरी के पैसों के लेन-देन को लेकर मृतक और आरोपियों के बीच विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जवान में पता चला था कि 13 मई को एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद राजू उर्डके आरोपियों के साथ मोटरसाइकिल से गया था, जिसके बाद वह वापस घर नहीं लौटा था।

पहले ही चार आरोपियों को किया जा चुका था गिरफ्तार :पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, पुष्टाछ के आधार पर 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रुपेश कवडे निवासी दुई ढाना सेल्टिया जिला छिंदवाड़ा, आधुप नरें निवासी बांमला जिला बैतूल, तेजीलाल उर्डके निवासी ढाकरवाड़ी जिला छिंदवाड़ा और एक विधि-विरुद्ध बांकरु शामिल थे। वहीं फरार आरोपी संजय उर्फ संजू पिता अनिल धुर्वे उम्र 20 वर्ष निवासी ढाकरवाड़ी थाना नवेगांव जिला छिंदवाड़ा पर पुलिस ने 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने लगातार तलाश के बाद आरोपी संजय उर्फ संजू को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। थाना बोरदेही में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

# जनपद

## बेटियों की शिक्षा, जनजातीय विकास और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का किया आह्वान

# प्रधानमंत्री का संकल्प, 2047 तक कोई भी बच्चा सिकल सेल से प्रभावित न रहे: राज्यपाल



### सिकल सेल उन्मूलन अभियान जन आंदोलन बने: केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया सिकल सेल मिशन-2047 देश को सिकल सेल मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अभियान है। उन्होंने कहा कि भीमपुर में सिकल सेल जांच मशीन का लोकार्पण जनजातीय एवं वंचित समुदायों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल उन्मूलन केवल स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन जागरूकता और जनभागीदारी का अभियान है। गांव-गांव तक जागरूकता पहुंचाकर आने वाली पीढ़ियों को इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री श्री उर्डके ने कहा कि बैतूल जिले में व्यापक स्तर पर सिकल सेल स्क्रीनिंग कर मरीजों एवं केरियर की पहचान की गई है, जिससे समय पर उपचार और परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है।

अभियान एक मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि भीमपुर में स्थापित नई जांच मशीन से अब क्षेत्र के लोगों की शीघ्र जांच हो सकेगी और समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा। कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि जिले में सिकल सेल उन्मूलन अभियान के अंतर्गत अब तक 8 लाख 62 हजार 332 हितग्राहियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। जिले में 1681 सिकल सेल डिजीज मरीज तथा 7162 सिकल सेल केरियर मरीज चिन्हित किए गए हैं। इसके

साथ ही 24 हजार 993 गर्भवती महिलाओं की भी सिकल सेल जांच की गई है।

उन्होंने सिकल सेल से प्रभावित मरीजों से नियमित उपचार कराने और संतुलित जीवनशैली अपनाने का आग्रह करते हुए कहा कि एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी में भी उपचार उपलब्ध हैं। उन्होंने तैलीय एवं बाहर के भोजन से बचने, पौष्टिक आहार लेने, नियमित व्यायाम करने तथा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

### सतपुड़ा वेली स्कूल के छात्रों ने कैम्ब्रिज परीक्षा में लहराया परचम, जिले को दिलाई वैश्विक पहचान

बैतूल। कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन (सीएआईई), यूनाइटेड किंगडम द्वारा आयोजित मार्च 2026 की कैम्ब्रिज लोअर सेकेंड्री एवं प्राइमरी चेकपॉइंट परीक्षा में सतपुड़ा वेली स्कूल, बैतूल के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। परिणामों में विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन को प्रमाणित किया है। कैम्ब्रिज लोअर सेकेंड्री चेकपॉइंट में निजस गोटी ने तीनों विषयों में शानदार प्रदर्शन करते हुए गणित में 43/50, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज में 50/50 तथा विज्ञान में 46/50 अंक प्राप्त किए। वंश राठौर ने गणित में 49/50 अंक हासिल कर सर्वोच्च प्रदर्शन किया। उन्हें इंग्लिश में 38/50 और विज्ञान में 37/50 अंक मिले। सुशय सुमन ने गणित में 46/50 और विज्ञान में 39/50 अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वहीं आधुप भील, कनिष्का गोटी, जुमाना हुसैन, अधिराज अतुलकर और मोशा खत्री ने भी सभी विषयों में सराहनीय परिणाम हासिल किए।

## ऑनलाइन दवा बिक्री और कॉर्पोरेट छूट के खिलाफ केमिस्टों का हल्लाबोल, धार जिले में 1550 से अधिक मेडिकल स्टोर बंद

धार। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रिगिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय आह्वान पर बुधवार को जिलेभर में दवा कारोबार पूरी तरह ठप रहा। ऑनलाइन दवा बिक्री और बड़े कॉर्पोरेट घरानों द्वारा दी जा रही भारी छूट के विरोध में जिले के 1550 से अधिक केमिस्टों ने अपनी दुकानें बंद रखीं। इस एक दिवसीय हड़ताल का व्यापक असर शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक साफ देखने को मिला। केमिस्टों के इस आंदोलन को चिकित्सा क्षेत्र से भी समर्थन मिला। विरोध के चलते जिले के निजी नर्सिंग होम की नियमित ओपीडी पूरी तरह बंद रही। हालांकि, राहत की बात यह रही कि अस्पतालों से इमरजेंसी (आपातकालीन) सेवाएं सुचारु रूप से चालू रखी गईं, जिससे गंभीर मरीजों को किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।

इन प्रमुख मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई: एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉ.



अशोक शास्त्री, सचिव आशीष बांगर ने बताया कि यह आंदोलन छोटे व्यापारियों के अस्तित्व को बचाने के लिए है। ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर तुरंत रोक लगाई जाए। कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा दवाओं पर दिए जा रहे भारी डिस्काउंट पर नियंत्रण किया जाए। बाजार में नकली दवाओं के अवैध कारोबार पर सरकार सख्त कार्रवाई करे। जिलाध्यक्ष डॉ. अशोक शास्त्री ने ऑनलाइन दवा व्यापार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऑनलाइन और बड़े कॉर्पोरेट डिस्काउंट के कारण छोटे और पारंपरिक कारोबारियों पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मेडिकल

व्यवसाय को खत्म करने की सोची-समझी कोशिश की जा रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ऑनलाइन माध्यमों से इन दिनों बाजार में नींद की दवाइयों (स्लीपिंग पिल्स) का दुरुपयोग बेहद बढ़ गया है, जिसकी गिरफ्त में देश की युवा पीढ़ी आ रही है। जूझ व्यापारियों ने इस बंद के माध्यम से अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। केमिस्ट एसोसिएशन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि सरकार और संबंधित विभागों ने उनकी मांगों को नहीं देखा है, तो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और अधिक संकट और राष्ट्रव्यापी रूप दिया जाएगा।

### भाजपा के दो दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग का मांडव में शुभारंभ, 7 सत्रों में संगठन और विचारधारा पर हुआ मंथन

# भाजपा राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए निरंतर कार्य कर रही है: मोघे

धार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026 के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी धार के दो दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग का बुधवार को ऐतिहासिक नगरी मांडव में विधिवत शुभारंभ हुआ। प्रशिक्षण वर्ग के पहले दिन सात अलग-अलग सत्र आयोजित किए गए, जिनमें पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक कार्यपद्धति, सरकार की उपलब्धियां, गरीब कल्याण योजनाएं तथा कार्यकर्ता विकास जैसे विषयों पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण वर्ग में जिलेभर से बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में भाजपा के पूर्व संगठन महामंत्री कृष्ण मुरारी मोघे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती संभाग प्रशिक्षण प्रभारी दिलीप पटौदिया, जिला प्रशिक्षण वर्ग प्रभारी नानूराम कुमावत, जिला संगठन प्रभारी सुभाष कोठारी, धार विधायक नीना वर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजवर्धनसिंह दत्तीगांव तथा पूर्व विधायक वेलसिंह भुरिया मंचासीन थे। शुभारंभ में सरस्वती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर मान्यार्पण और दीप प्रज्वलन व वंदेमातरम के साथ हुआ। भाजपा जिलाध्यक्ष महंत निलेश भारती ने संगठन की मजबूती पर जोर देते

हुए कहा कि भाजपा की वास्तविक शक्ति बृथ स्तर के कार्यकर्ता हैं और पार्टी को प्रत्येक बृथ पर मजबूत बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने प्रशिक्षण वर्ग को कार्यकर्ताओं के लिए वैचारिक एवं संगठनात्मक रूप से उपयोगी बताया। भाजपा का संगठन निरंतर प्रशिक्षण और अनुशासन के बल पर आगे बढ़ रहा है: मुख्य वक्ता कृष्ण मुरारी मोघे ने 'हमारा सैद्धांतिक अधिष्ठान' विषय पर विस्तार से विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती वैश्विक शक्ति से घबराई राष्ट्रविरोधी ताकतें देश में सामाजिक एवं आर्थिक अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन भाजपा राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए निरंतर कार्य कर रही है।

मोघे ने एकात्म मानववाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तथा भाजपा की पंचनिष्ठाओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प से प्रेरित संगठन है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानव दर्शन में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के उत्थान का विचार निहित है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भारतीयता की आत्मा बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति, परंपरा और राष्ट्र भावना भाजपा की विचारधारा का मूल आधार है। उन्होंने भाजपा की पंचनिष्ठाओं - राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, शोषणमुक्त एवं समतायुक्त समाज की स्थापना, जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस सत्र के अध्यक्षता अजजा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष रजनीश मालवीय ने की।



राजनीतिक विकेंद्रीकरण को कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बताया। दूसरे सत्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता राधेश्याम यादव ने 'विचार परिवार' विषय पर संबोधित किया। इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. शरद विजयवर्गीय ने की। यादव ने संबंद्धित किया। इस सत्र की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं विभिन्न अनुशासन संगठनों की भूमिका पर जानकारी दी। तीसरे सत्र में जिला प्रशिक्षण वर्ग प्रभारी नानूराम कुमावत ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ताओं को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस सत्र के अध्यक्षता अजजा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष रजनीश मालवीय ने की।

चौथे सत्र में संतोष मेहता ने 'कार्य विस्तार' विषय पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने संगठन के विस्तार, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने तथा बृथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया। इस सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने की।

पांचवें सत्र में खरगोन लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल ने केंद्र एवं राज्य सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं और उनके क्रियान्वयन में संगठन की भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। इस सत्र की अध्यक्षता भाजपा नेता डॉ. प्रह्लाद सिंह सोलंकी ने की।

छठवें सत्र में इंदौर महापौर पुष्पमित्र भागवत ने 'कार्य पद्धति' विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठनात्मक कार्यशैली, जनसंपर्क और आधुनिक कार्य प्रणाली पर अपने विचार रखे। इस सत्र की अध्यक्षता योगेश अग्रवाल ने की।

प्रशिक्षण वर्ग के पहले दिन के अंतिम एवं सातवें सत्र में विवेक भट्टारे ने 'व्यवहारिक विषय' पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने संगठन में व्यवहार, संवाद शैली, जनसंपर्क और कार्यकर्ता जीवन में अनुशासन की महत्ता पर प्रकाश डाला।

## संक्षिप्त समाचार

**सोनाघाटी में अवैध मुरुम उत्खनन पर 32 लाख 25 हजार का जुर्माना, पोक्लेन मशीन राजसात**

बैतूल (निप्र)। जिले के सोनाघाटी क्षेत्र में अवैध मुरुम उत्खनन के मामले में अपर कलेक्टर न्यायालय बैतूल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी पर 32 लाख 25 हजार रुपये की शक्ति अधिरोपित की है। साथ ही उत्खनन में प्रयुक्त पोक्लेन मशीन को शासन के पक्ष में अधिहरित करने के आदेश भी दिए गए हैं। प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से उप संचालक खनि प्रशासन बैतूल द्वारा प्रस्तुत मामले में बताया कि 15 जनवरी 2025 की रात लगभग 2:30 बजे थाना कोतवाली बैतूल पुलिस को मौजा सोनाघाटी स्थित खसरा नंबर 105/5 पर अवैध मुरुम उत्खनन की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां एक चैन माउटेड पोक्लेन मशीन से मुरुम उत्खनन करते हुए पाया गया। पुलिस जब मशीन को थाना ले जा रही थी, उसी दौरान दो खाली डम्पर क्रमांक एमपी 48 एच 5560 एवं एमएच 27 एक्स 0801 उत्खनन स्थल की ओर जाते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर दोनों वाहन चालक डम्पर छोड़कर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने दोनों डम्परों को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा कराया। अगले दिन सहायक खनि अधिकारी बैतूल एवं विभागीय अमले द्वारा स्थल निरीक्षण कर गड्ढों की नगई की गई, जिसमें कुल 3465 घनमीटर मुरुम उत्खनन होना पाया गया। जांच के दौरान पोक्लेन ऑपरैटर अजय फरकाड़े ने अपने बयान में बताया कि मशीन शेख निजाम निवासी टिकारी की है और उनके कहने पर रात में मुरुम निकालकर डम्परों से परिवहन किया जाता था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि अनावेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित है। हालांकि दोनों डम्परों की खाली अवस्था में जब्त किए जाने के कारण अवैध परिवहन में उनकी सलिप्तता प्रमाणित नहीं मानी गई। अपर कलेक्टर वंदना जाट ने आदेश पारित करते हुए मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18(6) के तहत शेख निजाम पर 32 लाख 25 हजार रुपये की शक्ति अधिरोपित की। साथ ही जसशुदा पोक्लेन मशीन को शासन के पक्ष में अधिहरित करते हुए उप संचालक खनि प्रशासन बैतूल को मशीन का पारदर्शी तरीके से निस्तारण करने तथा शक्ति राशि की वसूली के निर्देश दिए गए हैं।

**शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत युवक-युवतियों को दिया जा रहा है 45 दिवसीय प्रशिक्षण**

रायसेन (निप्र)। राज्य शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान युवक-युवतियों को सैन्य बल एवं अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों, पुलिस, होमगार्ड एवं निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए तैयार करने हेतु शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना-2026 प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत जिले के 87 बालक एवं 49 बालिकाओं को माता शबरी शासकीय कन्या शिक्षा परिसर रायसेन में 45 दिवसीय प्रशिक्षण आरंभ हो गया है। प्रशिक्षण स्थल शासकीय कन्या शिक्षा परिसर के सभागार में अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय ने सभी प्रतिभागियों को अनुशासन, नैतिक मूल्य, ईमानदारी की महत्ता बताते हुए प्रशिक्षण के निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पूर्ण उत्साह से प्रशिक्षण प्राप्त कर योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। सभी प्रतिभागियों को स्टेशनरी किट भी प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रभारी सहायक संचालक श्री नवीन गुप्ता, माता शबरी शासकीय कन्या शिक्षा परिसर के प्राचार्य श्री सुधीर जैन, अधीक्षिका श्रीमती लक्ष्मी परिहार, अधीक्षक श्री हरीप्रसाद सोनी तथा श्री चन्द्रशेखर यादव उपस्थित रहे।

**रायसेन में जनऔषधि केंद्र पर अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम आयोजित**

रायसेन (निप्र)। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार मेरा युवा भारत रायसेन द्वारा जिले में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत संचालित जन औषधि केंद्र पर अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं युवाओं को जन औषधि केंद्र की कार्यप्रणाली, उपयोगिता एवं समाज में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने जन औषधि केंद्र का भ्रमण कर वहां संचालित विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। जिला अस्पताल गंगण मे। जन औषधि केंद्र के संचालक श्री सुनील प्रजापति द्वारा बताया गया कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयों अत्यंत कम कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में बड़ी राहत मिलती है। प्रतिभागियों को दवाइयों के भंडारण, वितरण, बिलिंग प्रक्रिया, चिकित्सकीय पत्रों के अनुसार दवा उपलब्ध कराने तथा मरीजों को दी जाने वाली परामर्श सेवाओं की जानकारी दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि जन औषधि केंद्रों में उपलब्ध जेनेरिक दवाइयों गुणवत्ता के मानकों पर पूरी तरह खरी उतरती हैं तथा ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक सस्ती होती है। प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना का उद्देश्य देशभर में सस्ती एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

**कलेक्टर श्री विश्वकर्मा की अध्यक्षता में टीएल बैठक सम्पन्न**

# आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का समय सीमा में करें निराकरण: कलेक्टर विश्वकर्मा

रायसेन (निप्र)। कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा सीएम हेल्पलाइन, समय सीमा वाले पत्रों, विभागीय योजनाओं तथा अभियानों की सामाहिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने बैठक के प्रारंभ में आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निराकरण की प्रगति की जानकारी लेते हुए सभी एसडीएम तथा तहसीलदारों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का समयसीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री कार्य की भी समीक्षा करते हुए तहसीलदारों को प्राथमिकता से शेष कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी एसडीएम को सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की भी नियमित मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की विभागीय समीक्षा के दौरान जिला खाद्य अधिकारी को गंभीरतापूर्वक सीएम हेल्पलाइन निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार शहरी विकास, ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई, महिला बाल विकास सहित अन्य विभागों की सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की सामाहिक प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयावधि में संतुष्टिपूर्ण निराकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने नॉन अटेन्डेंट सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाते हुए गंभीरता के साथ निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का समयावधि में कराए निराकरण बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि आवेदनों का समयसीमा में निराकरण नहीं हो रहा है। अधिकारी इसे गंभीरता से लें और जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का समय



सीमा में निराकरण कराएं। साथ ही संबंधित आवेदक को भी निराकरण की कार्यवाही से अवगत कराएं। उन्होंने समाधान ऑनलाइन, सीएम ऑफिस से प्राप्त आवेदनों के निराकरण की भी समीक्षा की।

इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों और अवमानना प्रकरणों की भी समीक्षा करते हुए समय से जवाबदावा दर्ज कराने के लिए कहा। उपज के सुरक्षित भण्डारण और किसानों को शीघ्र राशि भुगतान के निर्देश कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि उपार्जन उपरांत किसानों को राशि भुगतान की कार्यवाही शीघ्रता से की जाए। साथ ही उपार्जन फसल का सुरक्षित भण्डारण भी कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि उपार्जन केन्द्रों पर बारदाने

की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी जनपद सीईओ को निर्देशित किया कि जहां हितग्राहियों को तीसरी किस्त वितरित हो गई है, वहां आवास शीघ्र पूर्ण कराएं। इसी प्रकार समग्र सीडिंग कार्य की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने कहा कि अभी भी 21523 नागरिकों की समग्र सीडिंग होना है, यह कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं। उन्होंने एक बगिया मां के नाम परियोजना, धरती आबा अभियान के तहत संचालित कार्य, अटल ग्राम सेवा सदन पंचायत भवनों के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। नागरिकों की स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने कार्यपालन यंत्रों को निर्देश दिए कि ग्रामीण

## विकासखंड नटेरन की ग्राम पंचायतों में कृषकों के समक्ष पहुंच रहा कृषि रथ

विदिशा (निप्र)। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है, कृषि वर्ष 2026 के शुभारंभ के साथ विकासखंड नटेरन के ग्राम रुसल्ली, डंगरवाडा एवं हड़ा में कृषि रथ कार्यक्रम में अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।

विदिशा जिले के प्रत्येक विकासखंड अंतर्गत निर्धारित ग्राम पंचायतों में कृषि रथ का नियमित भ्रमण किया जाएगा। प्रतिदिन ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि रथ के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध विभागों जैसे पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य पालन आदि से संबंधित योजनाओं एवं गतिविधियों की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाएगी। इस दौरान किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित कर नवीन एवं वैज्ञानिक तकनीकी सुधारों की जानकारी दी जाएगी। विकासखंड तकनीकी प्रबंधक श्री नरेंद्र सिंह रघुवंशी द्वारा कृषि रथ के माध्यम से जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, कीट एवं रोग प्रबंधन, कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उपाय, फसल विविधीकरण, विभागीय कृषि योजनाओं का प्रचार-प्रसार, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, ई-विकास प्रणाली अंतर्गत ई-टोकन उर्वरक वितरण व्यवस्था तथा पराली प्रबंधन



जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। डंगरवाडा में किया गया संवाद

आज दिनांक को कृषि रथ ग्राम डंगरवाडा पहुंचा, जहां उपस्थित कृषकों के साथ कृषि विस्तार अधिकारी श्री लक्ष्मण सिंह गुर्जर द्वारा नई ई-टोकन उर्वरक वितरण व्यवस्था एवं विभिन्न विभागीय योजनाओं पर चर्चा की गई। किसानों ने योजनाओं में गहरी रुचि दिखाई और अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। कृषि रथ अभियान के माध्यम से जिले के किसानों को आधुनिक, वैज्ञानिक एवं लाभकारी खेती की दिशा में प्रेरित कर किसान कल्याण वर्ष 2026 को सार्थक बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

## केसला में खेल के साथ मनोरंजन, व्यक्तिगत विकास और स्वास्थ्य पर जोर

नर्मदापुरम (निप्र)। खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश की अरोह 2026 योजना के अंतर्गत जनजातीय बाहुल्य विकासखंड केसला में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 01 मई 2026 से शुरू हुए ये शिविर तीन अलग-अलग स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं, ग्राम पंचायत जामनी के हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में प्रशिक्षण सुमित यादव द्वारा कबड्डी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खेल परिसर में प्रशिक्षक विकास कोरी के नेतृत्व में हॉकी के गुरु सिखाए जा रहे हैं, एवं



शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पथरोटा में प्रशिक्षक जगन वारसे द्वारा वालीबॉल एवं एथलेटिक्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर समन्वयक आरती शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण केवल खेल तक सीमित नहीं है। फिट

**ग्राम रुसल्ली एवं हड़ा के कृषकों ने विस्तारपूर्वक जाना कृषि से जुड़े विभागों की योजनाएं**

कृषि रथ ग्राम पंचायत रुसल्ली में पहुंचा जहां किसानों द्वारा शासन की कृषिगत योजनाओं को जानने एवं उनसे लाभ प्राप्त कर रहे कृषकों ने अपने विचार साझा किए इसके उपरांत कृषि रथ हड़ा में पहुंचा जहां उद्यानिकी विभाग से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री कुंदन सिंह द्वारा उद्यानिकी विभाग में चल रही प्रकृत विस्तार संबंधित योजनाओं मुख्यतः फलसब्जबीधसालाधमूल क्षेत्र विस्तार एवं पीएमएफएमई, जैविक खेती संबंधित योजना के विषय में कृषकों को जानकारी प्रदाय की गई।

## मप्र वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय नगाइच ने चुनी जवाबदेही नर्मदापुरम में किया गोदामों का औचक निरीक्षण

नर्मदापुरम (निप्र)। मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री संजय नगाइच ने पदभार ग्रहण करते ही 'सुविधा नहीं, जवाबदेही' का संदेश दिया है। अध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उपार्जित स्कंध का निजी गोदाम पूर्ण भर जाने की स्थिति में निगम के स्वनिर्मित गोदामों में 120 प्रतिशत तक भंडारण सुनिश्चित किया जाए। इन निर्देशों के धरातल पर क्रियान्वयन की हकीकत परखने के लिए अध्यक्ष श्री नगाइच ने शनिवार को नर्मदापुरम जिले का आकस्मिक दौरा किया। उन्होंने शासकीय वेयरहाउसिंग शाखा हथनापुर एवं पंवारखेडा के भंडारण केन्द्रों का निरीक्षण कर उपार्जन और भंडारण प्रक्रिया की सूक्ष्म जांच की। अध्यक्ष ने संयुक्त भागीदारी योजना के तहत अनुवर्धित निजी वेयरहाउस - साईं कृपा वेयरहाउस चौलाय, बी.जी. वेयरहाउस चौलाय एवं रघुवीर वेयरहाउस डोलरिया का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान निजी गोदामों में अमानक गेहूं का भंडारण पाए जाने पर उन्होंने समिति प्रबंधक एवं

सर्वेयर को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि साफ-सुथरा एवं एफएक्यू मापडंड का गेहूं ही खरीदा जाए। किसी भी स्थिति में अमानक गेहूं का भंडारण बर्दाश्त नहीं होगा। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने वेयरहाउस संचालकों को एप्रोच रोड दुरुस्त करने और श्रमिकों की निर्भरता कम करने के लिए मैकेनाइजेशन अपनाने को प्रेरित किया। साथ ही वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के गोदामों में दीर्घ अवधि से भंडारित स्कंध के कारण हो रही भंडारण हानि को कम करने हेतु ठोस कार्ययोजना बनाने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देशित किया। श्री नगाइच ने सभी शाखा प्रबंधकों को पूर्ण पारदर्शिता, ईमानदारी और जर्नल के प्रति सकारात्मक सोच के साथ अनुशासन में रहकर निगम हित में कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय प्रबंधक नर्मदापुरम श्री अतुल सोरटे, क्षेत्रीय प्रबंधक भोपाल श्री राजेश अग्रवाल, जिला प्रबंधक मप्रवेल्कोका श्री वासुदेव दवण्डे, शाखा प्रबंधक हथनापुर श्री गौरव पटेल, शाखा प्रबंधक बानापुरा श्री शिवराज राजपूत, शाखा प्रबंधक इटारसी श्री नंदकिशोर बंदी एवं शाखा प्रबंधक पंवारखेडा श्री विनोद बिसारे उपस्थित रहे।

## बाढ़ आपदा पूर्व तैयारियों के संबंध में दिए निर्देश

विदिशा (निप्र)।प्रभारी कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर ने आज लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ एवं राहत कार्यों के संबंध में किए जाने वाले प्रबंधों हेतु तैयारियों संबंधी बैठक में बाढ़ आपदा से निपटने के लिए अभी से ही सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। प्रभारी कलेक्टर श्री डामोर ने विशेष कर बिजली विभाग को निर्देश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के दौरान खतरा निर्मित होने की संभावना है उन जगहों का पहले से ही चिन्हांकन कर सुरक्षा के इंतजाम कर लिए जाएं। निर्माण विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी सड़कें व कुल पुलिया डब क्षेत्र में आती हैं उनका चिन्हांकन कर सुरक्षा की दृष्टि से प्रबंध सुनिश्चित करें, इसके अलावा सभी तहसीलों में स्थापित वर्षा मापी यंत्रों की जानकारी की प्रतिदिन एंटी करें व इसकी जानकारी जिला कार्यालय को भी उपलब्ध कराई जाए।



बैठक में जिले के बांध एवं भराव क्षमता की जानकारी भी दी गई। प्रभारी कलेक्टर श्री डामोर ने कहा कि उन स्थानों का चिन्हांकन करें जहां नदी किनारे आम नागरिक निवास कर रहे हैं और उन्हें बाढ़ की स्थिति निर्मित होने के पहले विस्थापित करें। उनके ठहरने के इंतजाम, भोजन-पानी सहित बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं।

प्रभारी कलेक्टर श्री डामोर ने बाढ़ बचाव की पूर्व तैयारियों तथा पूर्व प्रबंधों में सुधार, सुझाव पर आधारित कार्यों के क्रियान्वयन को त्वरित संपादन कराने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि आगामी वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए जिले में बाढ़ आपदा से निपटने पहले से ही अलर्ट हो जाएं, नगर पालिका क्षेत्र तथा

ग्रामीण क्षेत्र का चिन्हांकन कर लें जिन क्षेत्रों में पूर्व में बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई थी वहां के वाई एवं ग्रामीण क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां बाढ़ से निपटने के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करें। उन्होंने नगरपालिकाओं के अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि अभी से ही नगरीय क्षेत्र के वाई में नालों और नालियों की साफ सफाई कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि पानी निकासी होने में समस्या उत्पन्न ना हो और बाढ़ जैसे हालात ना बनें। प्रभारी कलेक्टर श्री डामोर ने सभी एसडीएमों को भी निर्देश दिए हैं कि खंड स्तर पर भी आपदा पूर्व तैयारी कर बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु अभी से ही इंतजाम कर लें। इसके साथ ही उन्होंने विदिशा जिले के पुल-पुलियों, रिपटा इत्यादि से मिट्टी व अनावश्यक मलबे को हटाए जाने के निर्देश भी दिए हैं ताकि वर्षा ऋतु में आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु के दौरान पुल-पुलियों पर यदि पानी हो तो वाहन चालकों को

पुल-पुलियों से आवागमन ना करने दिया जाए खासकर यात्री बसों को पुल-पुलियों पर अत्यधिक पानी होने पर निकलने ना दिया जाए इसके लिए बेरीकेट्स लगाकर पुल-पुलियों की निगरानी की जाए ताकि बाढ़ आपदा में कोई जनहानि की घटना घटित ना हो। प्रभारी कलेक्टर श्री डामोर ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में विशेष कर जिले में स्थित जर्जर भवनों का चिन्हांकन कर भवन मालिकों को नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भवन जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं। उन्हें नोटिस दे या स्वयं अपने स्तर पर ध्वस्त करने के कार्यों का संपादन करें, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके। इसके अलावा उन्होंने शासकीय भवन जो जर्जर हालत में है विशेष कर स्कूल, आंगनबाड़ी या पशुपालन विभाग के भवन उन्हें यांशशीर्ष शिफ्ट कर लिया जाए। विशेष ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि या पशुहानि ना होने पाए।

## राइट विलक

## आखिर इंसानी जान की कीमत आवारा कुत्ते की जान से ज्यादा है....



अजय बोकिल

लेखक सुबह सवरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं। संपर्क- 9893699939 ajayborkil@gmail.com

सु प्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में देश में आवारा और खतरनाक कुत्तों को लेकर किसी भी तरह की सहानुभूति और करुणा दिखाने की जगह इंसानी जिंदगी पर मंडराते खतरे को रोकने के लिए पागल और खतरनाक कुत्तों को मारने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सम्बन्धित अधिकारी, पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों और दूसरे लागू कानूनी प्रोटोकॉल के मुताबिक, कानूनी तौर पर मंजूर उपाय कर सकते हैं, जिनमें उन कुत्तों को मारना भी शामिल है, जो लाइलाज बीमार हैं, पागल या साफ तौर पर खतरनाक और आक्रामक हैं। ताकि इंसानी जिंदगी और सुरक्षा पर मंडराते खतरे को असरदार तरीके से खत्म किया जा सके। यही नहीं सर्वोच्च अदालत ने सभी हाई कोर्ट्स को इस मामले की निगरानी के निर्देश दिए हैं, साथ ही लापरवाह अधिकारियों पर अवमानना कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त आदेश से जहां श्वान पीड़ितों में राहत है, वहीं श्वान प्रेमियों में गहरी निराशा है। ये लोग कुत्तों को इस तरह मारे जाने को 'घटती मानवीय गरिमा' से जोड़कर इसकी आलोचना कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ यही है कि आवारा कुत्ते के काटे जाने से एक बेगुनाह इंसान के मर जाने की तुलना में खतरनाक कुत्ते को जान से मार देना मानवीय गरिमा को घटाना है। कुत्तों के पक्ष में खड़े ज्यादातर पशु प्रेमी जो हैं, जिनका साबका अपने किसी करीबी की रेबीज से मौत से शायद नहीं पड़ा है।

बेशक, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भी बहस शुरू हो गई है। लेकिन यह मान लेना कि इंसानी जान की कीमत एक कुत्ते की जान की तुलना में कमतर है, खुद को धोखे में

रखने जैसा है। जान चाहे इंसान की हो या फिर चोंटी की, जान, जान है, लेकिन वह क्यों और कैसे ली जा रही है या गंवाई जा रही है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

देश में आवारा कुत्तों की संख्या करीब 6 से 7 करोड़ बताई जाती है यानी कि औसत हर 20 भारतीयों के पीछे एक आवारा कुत्ता है तथा इनमें से एक फीसदी भी खतरनाक या पागल होंगे तो इनकी तादाद 6-7 लाख से कम नहीं होगी। इतने कुत्ते कितने लोगों की जान ले सकते हैं, यह सोचें तो भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनमें पालतू कुत्तों की संख्या शामिल नहीं है, क्योंकि वो सुरक्षा कारणों से, रस्सी का दिखावा करने की चाहत में अथवा शुद्ध श्वान प्रेम के कारण पाले जाते हैं। चिंता की बात यह है कि हमारे देश में आवारा कुत्तों की आबादी बढ़ने, उनकी प्रजनन क्षमता पर अंकुश लगाने तथा किन्हीं कारणों से पागल और हिंसक हो चुके कुत्तों पर नियंत्रण की कोई कारगर व्यवस्था नहीं है। कुछ स्थानों पर कुत्तों की नसबंदी वगैरह की जाती है, लेकिन वो बहुत कारगर नहीं है। कुछ आवारा कुत्तों को पकड़कर दूर कहीं जंगल में छोड़ दिया जाता है और उनमें से ज्यादातर वापस अपनी गलियों में लौटकर 'शेर' हो जाते हैं। यूँ कुत्ता मनुष्य का दोस्त है, लेकिन हिंसक होने पर वह सारे रिश्ते भूल जाता है। भारत में हर साल कुत्ता काटने से करीब 15 से 20 हजार लोगों की मौत होती है। कुत्ता काटने के बाद जो लोग समुचित इलाज के अभाव में रेबीज का शिकार हो जाते हैं, उनकी हालत कुत्तों से भी बदतर हो जाती है। लेकिन श्वान प्रेमी कुत्तों के इस नकारात्मक पहलू को करुणा की दरी के नीचे खिसकाना बेहतर समझते हैं। वैसे यह मामला पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट में आया था। जस्टिस विक्रम नाथ,

जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजलिया की बेंच ने आवारा कुत्तों के खतरे को लेकर स्वतः संज्ञान लिए गए मामले में यह निर्देश दिया था कि अस्पतालों, बस अड्डों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों जैसी सार्वजनिक जगहों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अधिकारियों को ऐसे परिस्थितों से मौजूद आवारा कुत्तों को हटाकर उनकी नसबंदी करानी होगी। इसके बाद उन्हें डॉग शैल्टर में भेजना होगा। हालांकि तब इस फैसले की व्यावहारिकता पर सवाल उठे थे और कुत्तों के साथ इस तरह के व्यवहार को अमानवीय (या अश्वाननीय) कहा गया था। इसके खिलाफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं कोर्ट में दायर हुई थीं, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों को वापस लेने से इंकार कर दिया। कुत्तों के प्रति लाख सहानुभूति के बाद भी कड़वी सच्चाई यही है कि आज आवारा कुत्ते बच्चों और बुजुर्गों के लिए मौत का परवाना बन गए हैं।

यद्यपि कोर्ट के इस आदेश पर सख्ती से पालन पर अभी भी प्रश्न निरूद्ध है। बावजूद इसके कि कोर्ट ने माना कि आवारा कुत्तों के काटने से लोगों की जान जाने की समस्या बेहद गंभीर रूप ले चुकी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुरक्षित व्यवस्था बनाने में नाकाम अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी की जा सकती है।

इसमें दो राय नहीं कि कुत्तों को भी जीने का और पूरी गरिमा के साथ जीने का हक है। मूक प्राणियों के प्रति संवेदना मानवीय गुण है। लेकिन असल सवाल यह है कि कुत्ता अगर 'श्वान' न

रहकर सचमुच 'कुत्ता' हो जाए तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या वह अपनी जान गंवाने का जोखिम उठाता रहे और कुत्तों की जान बख्शाता रहे? जो लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, वो कुत्तों के मानवाधिकार को मानवीय गरिमा की रक्षा के साथ जोड़कर देख रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस जाले को यह कहकर साफ किया है कि 'गरिमा के साथ जीने के अधिकार में यह अधिकार भी शामिल है कि व्यक्ति कुत्तों के हमलों के डर के बिना स्वतंत्र रूप से जीवन जी सके। लिहाजा राज्य मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। अदालत भी उन कठोर जर्मनी हकीकतों से आँखें नहीं मूंद सकती, जहाँ बच्चे, विदेशी यात्री और बुजुर्ग कुत्तों के काटने की घटनाओं का शिकार हुए हैं। संविधान ऐसे समाज की कल्पना नहीं करता, जहाँ बच्चों और बुजुर्गों का जीवन केवल शारीरिक ताकत या क्रिस्म के भरसे हो।' जाहिर है कि यह फैसला पशु संवेदना के खिलाफ नहीं है। केवल आवारा, हिंसक और पागल हो चुके कुत्तों को लेकर है। आवारा कुत्तों का हर संभव इलाज किया जाए, उन्हें खाना खिलाया जाए, उन्हें आवारा बनने और इंसान पर हमला करने से रोका जाए इत्यादि बातें सैद्धांतिक तौर पर रंजक और आदर्शवादी लगती हैं। लेकिन जरा उन परिवारों के दुख पर भी निगाह डालिए, जिन्होंने आवारा कुत्ते के काटे जाने के बाद अपने किसी परिजन को खोया है। इनमें कई तो ऐसे फूल हैं, जो खिलने के पहले ही मुझा गए और कई ऐसे हैं, जिन्होंने ऐन जवानी अथवा बुढ़ापे में असमय अपने प्राण गवा दिए हैं। और यह कोई पशुप्रेम की राह में दी गई शहादत नहीं है बल्कि आवारा कुत्तों को दी गई विवशताजनित अबाध हूट अथवा कुत्तों को मानव से भी ज्यादा जरूरी प्राणी मान लेने के दुराग्रह का नतीजा है।



## सांपके काटनेसे युवककी मौत

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कजलीखेड़ा में सांप के काटने से व्यक्ति की 8 दिन चले इलाज के बाद मौत हो गई। बुधवार दोपहर बाँडी का पीएम कराने के बाद परिजनों को सौंप दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक अनीस खान पिता मुनीर खान (50) निवासी बोरदा कजलीखेड़ा बिजली विभाग में अटैच कार को ड्राइव करने का काम करते थे। 12 मई को घर के पास खड़े थे। अचानक कुछ चुभने जैसा महसूस हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि जहरीली चीज ने काटा है। तब परिजनों ने घर आकर देखा तो घर की सीढ़ियों के करीब एक छेद में सांप दिखा। जिसके बाद उन्होंने सांप को रेस्क्यू कराया, जिसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया।

## प्रदेश में चितनीय स्थिति पानी के लिए कुएं में उतर रही महिलाएं

● देवास में पानी के लिए चक्काजान, खरगोन में पंचायत का घेराव, बड़वानी में गधों से पानी की सप्लाई



भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ पेयजल संकट गहराता जा रहा है। कहीं महिलाएं जान जोखिम में डालकर कुओं में उतर रही हैं तो कहीं लोग सूखी नदी-नालों में झिरियां खोदकर मटमैला पानी पीने को मजबूर हैं। कई गांवों में लोग किलोमीटरों दूर से पानी ला रहे हैं, जबकि कुछ जगह नल से बंदबंदार और कीड़े वाला पानी सप्लाई हो रहा है। प्रदेश के कई जिलों में चिंताजनक हालात सामने आए। खरगोन के टमला गांव में एक महीने से जल संकट है। 5-6 दिन से नल सूखे हैं और तीन दिन में सिर्फ एक घंटे पानी मिल रहा है। नाराज ग्रामीणों ने चक्काजान किया। सीहोर के रामगढ़ समेत कई गांवों में महिलाएं कुओं में उतरकर या

सूखी नदियों में झिरियां खोदकर पानी जुटा रही हैं। कई जगह 2 किमी दूर से कपड़े से छानकर पानी लाना पड़ रहा है। बैतूल के हरिमऊ गांव में नल-जल योजना बंद है और हैंडपंप सूख चुके हैं। करीब एक हजार आबादी 5 किमी दूर गढ़े कुएं के भरोसे है। महिलाएं-बच्चे घंटों लाइन में लग रहे हैं। रायसेन के कोकलपुर गांव में ग्रामीणों ने सरकारी कुएं पर दबाव के कब्जे का आरोप लगाया है। 2 हजार आबादी को दिनभर में सिर्फ 3-4 क्यूपा पानी मिल रहा है। मंदसौर के कई इलाकों में कंठ महीने से नलों में कीड़े, कचरा और बंदबंदार पानी आ रहा है। सतना के कई गांवों में लोग 2 किमी दूर से पानी लाने को मजबूर हैं।

## कौशल प्रशिक्षण से बढ़ रहा बेटियों का आत्मविश्वास

भोपाल (नप्र)। प्रदेश की बेटियां अब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की योजनाएं उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के बेहतर अवसर दे रही हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में महिलाएं अब तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ रही हैं। कौशल प्रशिक्षण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है।

प्रदेश में 934 आईटीआई हैं। इनमें 290 शासकीय और 644 निजी आईटीआई शामिल हैं। इन संस्थानों में युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2025 में शासकीय आईटीआई में 94.55 प्रतिशत प्रवेश हुआ। यह अब तक का सर्वाधिक प्रवेश प्रतिशत है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शासकीय आईटीआई में 35 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इसका अच्छा परिणाम दिखाई दे रहा है।

प्रदेश की आईटीआई में वर्तमान में 71 आधुनिक ट्रेड्स में 15 हजार से अधिक महिला प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा), स्ट्रेनोग्राफर हिन्दी और इलेक्ट्रिशियन जैसे ट्रेडों में बड़ी संख्या में बेटियाँ प्रशिक्षण ले रही हैं। यह बदलते माहौल और बेटियों के बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाता है। अब बेटियां नए क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने भविष्य को मजबूत बना रही हैं।

महिलाओं को सुरक्षित और बेहतर वातावरण देने के लिए प्रदेश में 7 शासकीय महिला आईटीआई संचालित की जा रही हैं। वहीं 56 शासकीय आईटीआई में महिला छात्रावास सुविधा उपलब्ध है। इनमें



Premiata Rahangdale Training Officer Govt. Divisional ITI Bhopal, MP

3400 से अधिक सीटें हैं। इससे दूर-दराज क्षेत्रों की बेटियों को भी प्रशिक्षण का अवसर मिल रहा है।

कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का फोकस केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है। विभाग महिलाओं को रोजगार से जोड़ने पर भी लगातार काम कर रहा है। विशेष महिला प्लेसमेंट ड्राइव के माध्यम से 777 महिला प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मिला है। इंदौर स्थित ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा 509 महिलाओं को निःशुल्क वाहन संचालन प्रशिक्षण दिया गया। इससे महिलाओं में आत्मनिर्भरता का भाव और मजबूत हुआ है।

महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विभिन्न

छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग और निधन वर्ग की 13 हजार से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति मिल रही है। इससे बड़ी संख्या में बेटियों को प्रशिक्षण जारी रखने में मदद मिल रही है।

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी बेटियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। योजना के अंतर्गत हजारों बेटियों को उद्योगों में ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग का अवसर मिला है। प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों में 5660 बेटियाँ शामिल हैं। सागर की सुश्री सैल रजक और रायसेन की सुश्री लिया जैसी युवतियां प्रशिक्षण के बाद रोजगार प्राप्त कर चुकी हैं। अब वे अपने परिवार को आर्थिक सबल प्रदान कर रही हैं।

महिलाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जीवन तरंग कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग 3000 बेटियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं यूएन वीमेन के सहयोग से बेटियों को स्टैम और सॉफ्ट स्किल्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इससे बेटियाँ एडवॉकेट तकनीकी और नए कार्यक्षेत्रों से जुड़ रही हैं।

परम फाउंडेशन के माध्यम से संचालित आईटीआई कौशल कॉलेजों में भी बड़ी संख्या में बेटियाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। धार जिले के संतरापुर आईटीआई में संचालित कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों का शत-प्रतिशत प्लेसमेंट हुआ है। इससे बेटियों के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार हुए हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत भी 64 हजार से अधिक बेटियों को कौशल प्रशिक्षण का लाभ मिला है।

## आईटी हॉस्टल में गांजा पार्टी पकड़ी

● डीएवीवी के सख्त कार्रवाई के संकेत ● तीन छात्र निलंबित, एक का एडमिशन समाप्त करने की तैयारी

इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईटी) के छात्रावास में सामने आए नशे के मामले के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस जांच के एक सप्ताह बाद संस्थान ने चार विद्यार्थियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तीन विद्यार्थियों को एक सत्र के लिए निलंबित कर दिया है, जबकि एक विद्यार्थी का प्रवेश समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पिछले मंगलवार को नशाखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने आईटी छात्रावास में छपा मारा था। कार्रवाई के दौरान चार इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को गांजा सेवन और मादक पदार्थों से जुड़े मामले में पकड़ा गया था। पूछताछ में ऐसे लोगों के नाम भी सामने आए, जो कथित रूप से छात्रावासों और शिक्षण संस्थानों



तक नशीले पदार्थ पहुंचाने का काम करते थे।

चार छात्र हिरासत में - कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गोल्डन नेस्ट मुंबई निवासी आयुष झा, देवास के राजाराम नगर निवासी विवेक शर्मा, मुर्ना के सबलगाड़ निवासी उमंग अग्रवाल और नर्मदापुरम

निवासी दीपांशु अहिरवार को हिरासत में लिया था। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी आईटी प्रशासन को भेजी। मामले की गंभीरता को देखते हुए संस्थान की अनुशासन समिति ने चारों विद्यार्थियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की। मामले की रिपोर्ट कुलगुरु डॉ. राकेश

सिंघई को सौंपी गई। आईटी के निदेशक डॉ. प्रतीप बंसल ने बताया कि बीतेक तृतीय वर्ष के एक विद्यार्थी और प्रथम वर्ष के दो विद्यार्थियों को जुलाई से दिसंबर 2026 तक एक सत्र के लिए निलंबित किया गया है। इस अवधि में वे किसी भी कक्षा, प्रयोगशाला, परीक्षा या संस्थान की अन्य गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे। वहीं एक अन्य विद्यार्थी का प्रवेश समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय प्रशासन का संदेश- विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि होस्टल्स में अनुशासन बनाए रखने और नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कठोर कदम उठाना आवश्यक है। प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्ती जारी रहेगी, ताकि विद्यार्थियों में अनुशासन का भय बना रहे और शिक्षण वातावरण प्रभावित न हो।

## एआई की मदद से सिंहस्थ-2028 में होगा सबकुछ

गूगल क्लाउड इंडिया के साथ सीएम मोहन यादव की हुई मीटिंग



सरकार का एक बड़ा करार होने जा रहा है। सरकार और गूगल क्लाउड के सहयोग से इंदौर में सेंटर ऑफ एवसीलेंस की स्थापना की जा रही है। सेंटर की स्थापना के लिए जल्द ही एमओयू भी साइन किया जाएगा। इस सेंटर से 10 हजार से अधिक एआई डेवलपर्स को जोड़ा जाएगा, जो मध्यप्रदेश सहित पूरे देश और साथ ही ग्लोबल को एआई की रीयल टाइम नीड टैक्निकल सपोर्ट उपलब्ध कराएंगे।

## सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में एआई की मदद

गूगल के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को बताया कि एआई समित के दौरान मप्र सरकार से अभूतपूर्व समर्थन और सहयोग मिला। इससे प्रेरित गूगल क्लाउड द्वारा प्रदेश के प्रमुख विभागों कृषि, शिक्षा, वन, महिला बाल विकास सहित अन्य विभागों को एआई से सशक्त किया जा रहा है। सिंहस्थ 2028 आयोजन की तैयारियों में भी एआई सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिंहस्थ के दौरान भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक संचालन, नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को भी अत्याधुनिक एवं तकनीकी आधारित बनाया जा सकता है।

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की गूगल क्लाउड इंडिया के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। मीटिंग के दौरान एमपी में स्थापित होने वाले मेगा डेटा सेंटर और सिंहस्थ-2028 को लेकर चर्चा हुई है। सिंहस्थ में एआई की मदद से अच्छी व्यवस्था और प्लानिंग की जाएगी। इंदौर में सेंटर ऑफ एवसीलेंस की स्थापना बैठक में अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि गूगल क्लाउड इंडिया के साथ राज्य